



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1974/कार्तिक 25, 1896
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1974/KARTIKA 25, 1896

इस भाग में सिमल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1974

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1974

कां० प्र० 2973—भारत सरकार, मन्त्रिमण्डल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कां० आ० सं० 2075, दिनांक 1 अगस्त, 1974 के हिन्दी पाठ में, जो भारत के राजपत्र, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) के पृष्ठ 2253 पर, 17 अगस्त, 1974 को प्रकाशित हुआ है,

पृष्ठ 2253 पर

उक्त आदेश की गानवी पंक्ति में,

“गोलपुरी” शब्द के स्थान पर “गोलसुरी” पढ़।

[स० 228/21/74-एबीडी-2]

बी० सी० बजानी, अवर सचिव

कां० प्र० 2974.—यत् निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 141 बरहुट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जे० बी० बेसरा, ग्राम धरमपुर, पो० पटना, जिला सहायपुरगना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्घीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यत् उक्त उम्मीदवार ने उसे रायक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्याख्योचित्य नहीं है,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जे० बी० बेसरा को समद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०-सं०/141/72(102)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 5th September, 1974

ORDERS

S.O. 2974.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri J. B. Besra, Village Dharampur, P. O. Pathna, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 141-Barhait constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri J. B. Besra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/141/72(102)]

का०प्रा० 2975.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 141-बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहन हेमराम, ग्राम धरमपुर, पो० पतना, भाया बरहरवा, जिला संथालपरगना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और; यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मोहन हेमराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०-सं०/141/72(103)]

S.O. 2975.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohan Hemram, Village Dharampur, P.O. Pathna via Barharwa, Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly

from 141-Barhait constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohan Hemram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/141/72(103)]

का०प्रा० 2976.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 141-बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मीसि मरंडी, ग्राम मनमसी, पो० बरहेट, जिला संथालपरगना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मीसि मरंडी को समद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार वि० सं०/141/72(104)]

S.O. 2976.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Misi Marandi, Village Sanmani, P.O. Barhait, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 141-Barhait constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Misi Marandi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/141/72(104)]

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1974

का. अ. 2977.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69-जैतपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमर सिंह, गांव तथा पो. मलगा, जिला गण्डोल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

यत्, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमर सिंह को सदन के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं. मं.प्र.वि.सं/69/72(52)]

New Delhi, the 19th September, 1974

S.O. 2977.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amar Singh, Gram and Post Malga, District Shandol who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 69-Jaitpur (ST) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/69/72(52)]

का. अ. 2978.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 161-गोपालपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लखन जयसवाल, ग्राम परबत्ता, पो. माहु परबत्ता भाया नौगछिया, जिला भागलपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य नहीं है ;

यत्, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लखन जयसवाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-वि.सं/161/72(111)]

S. O. 2978.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lakhman Jaiswal, Village Parvatta, P. O. Sahu Parvatta via Nawgachia, District Bhagalpur who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 161-Gopalpur constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lakhman Jaiswal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. BR-LA/161/72(111)]

का. अ. 2979.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 220-बाहुनिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लखिचन्द राम, ग्राम मचिघान्, पो. मुठानी, शाहाबाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

यत्, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लखिचन्द राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-वि.सं/220/72(114)]

S. O. 2979.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lakhi Chand Ram, Village Machiaon, P.O. Muthani, Shahabad (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 220-Mohania (SC) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lakhi Chand Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-I A/220/72(114)]

का. प्रा. 2980.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 158-कटनगाव निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अरविन्द नाथ सिन्हा, सिद्धेश्वर सदन, नया जबकनपुर, पटना-1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अरविन्द नाथ सिन्हा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कारावधि के लिए निर्हित घोषित करता है।

[सं बिहार-वि० सं/158/72(110)]

S. O. 2980.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Arvind Nath Sinha, Sedheshwar Sadan, Naya Jakkampur, Patna-1 who was contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 158-Colgong constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Arvind Nath Sinha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-I A/158/72(110)]

का० प्रा० 2981.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-बिहपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम देव शर्मा, ग्राम अमरपुर, पो० जिला बभनगामा (भाया बिहपुर), जिला भागलपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम देव शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कारावधि के लिए निर्हित घोषित करता है।

[सं बिहार-वि० सं/162/72(106)]

S.O. 2981.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Deo Sharma, Village Amarpur, P.O. Babhan-gama (via Bihpur) District Bhagalpur who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 162-Bihpur constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Deo Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/162/72(106)]

का. प्रा. 2982.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 148-मारठ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बालेश्वर प्र० राय, ग्राम गजियाडीह, पन्नालय मारठ, जिला संथाल परगना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बालेश्वर प्र० राय को संसद के किसी

भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है।

[सं बिहार-वि०स०/148/72(109)]

S. O. 2982—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Waleshwar Pro. Rai, Village Gajadih, P. O. Sarath, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 148-Sarath constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Waleshwar Pro. Rai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/148/72(109)]

क्र० प्रा० 2983.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 151-जर्मुन्डी निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नगदी प्रसाद राय, ग्राम खेरवा, पो० मारवा, जिला संथाल परगना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिनियम द्वारा निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पत्क सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यावृत्तिय नहीं है,

अतः अथ उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री नगदी प्रसाद राय को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है।

[सं बिहार-वि०स०/151/72(118)]

S. O. 2983.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nagdi Prasad Rai, Village Khairwan, P.O. Sarwan, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 151-Jarmundi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nagdi Prasad Rai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/151/72(118)]

क्र० प्रा० 2984.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 151-जर्मुन्डी निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सूर्यदेव मुर्मू, ग्राम सरैया, पो० चुलिया (वर्तमान) धर्ममारा जिला संथाल परगना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिनियम द्वारा निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार, ने, उसे सम्पत्क सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यावृत्तिय नहीं है;

अतः अथ, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री सूर्यदेव मुर्मू को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है।

[सं बिहार-वि०स०/151/72(119)]

S. O. 2984.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suryadev Murmu, Village Saraiya, P. O. Chulia, at present Ghormara, Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 151-Jarmundi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Suryadev Murmu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/151/72(119)]

क्र० प्रा० 2985.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 155-गोशु निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री त्रिवेनी झा ग्राम गोरमंडा पो० बपरी जिला संथाल परगना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिनियम

अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री त्रिवेनी झा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० सं०/155/72(107)]

S. O. 2985.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Triveni Jha, Village Gorsanda, P. O. Chapari, District santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 155-Godda constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Triveni Jha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this

[No. BR-LA/155/72(107)]

क्र० आ० 2996.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 155-गोडा निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हृदय नारायण भगत, ग्राम तुलसी किन्ना, पो० पथरगामा, जिला संभल परगना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियम द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री हृदय नारायण भगत को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० सं०/155/72(108)]

S. O. 2986.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hariday Narayan Bhagat, Village Tulsī Kitta, P.O. Pathargama, District Santhal Parganas who, was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 155-Goda constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hariday Narayan Bhagat to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/155/72(108)]

क्र० आ० 2987.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 266-बरही निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अलाउद्दीन अन्सारी, ग्राम बरही, हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अलाउद्दीन अन्सारी का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० सं०/266/72(112)]

S. O. 2987.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Alaudin Ansari, Village and P. O. Barhi, District Hazaribagh (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 266-Barhi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Alaudin Ansari to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/266/72(112)]

क्रा० प्र० 2988.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 266-बरही निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रहलाद सिंह ग्राम-पो० कदमा, जिला हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तख्तीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण के निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री प्रहलाद सिंह को सदन के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है।

[स० बिहार-वि०स०/266/72(113)]

S. O. 2988.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prehlad Singh, Village & P. O. Kadma District Hazaribagh, who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 266-Barhi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prehlad Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. BR-LA/266/72(113)]

नई दिल्ली, ता० 23 मितम्बर, 1974

क्रा० प्र० 2989.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 170-शाखा निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कैलाश यादव, ग्राम बलियागोह, पो० रजला भाया शाखा (मुंगेर) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तख्तीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण से निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री कैलाश यादव को सदन के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है।

[स० बिहार-वि०स०/170/72(120)]

New Delhi, the 23rd September, 1974

S.O. 2989.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kailash Yadav, Village Baliadih, P. O. Rajla via Jhajha, District Monghyr who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 170-Jhajha constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kailash Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/170/72(120)]

नई दिल्ली, ता० 24 मितम्बर, 1974

क्रा० प्र० 2990.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 176-सूर्य-गढ़ा निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गंगा प्रसाद सिंह यादव, ग्राम-पन्नामय शिवकुण्ड, जिला मुंगेर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तख्तीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण से निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री गंगा प्रसाद सिंह यादव को सदन के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है।

[स० बिहार-वि०स०/170/72(121)]

New Delhi, the 24th September, 1974

S. O. 2990.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ganga Prasad Singh Yadav, Village & P.O. Sheokund, District Monghyr who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 176-

Surajgarha constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ganga Prasad Singh Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/176/72(121)]

नई दिल्ली ता० 25 सितम्बर, 1974

का० प्रा० 2991.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 6-दिमनी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तोता राम, ग्राम पोरसा, माजरा, मानसपुरा, पो० पोरसा, तहसील ग्रामवाह, जिला मुरेना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री तोता राम को संसद् के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि० म०/6/72(56)]

New Delhi, the 25th September, 1974

S. O. 2991.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tota Ram, Village Porsa, Majra, Mansoorpur, Post Porsa, Tahsil Ambah, District Morena who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 6-Dimni constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tota Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/6/72(56)]

का० प्रा० 2992.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 6-दिमनी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री छोटईया, ग्राम बादोखार, पो० मुरेना, जिला मुरेना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रिति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में यत्नकर रहे हैं,

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री छोटईया को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि० म०/6/72(57)]

S. O. 2992.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chhotaiya, Village Badokhar, Post Morena, District Morena who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 6-Dimni constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chhotaiya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/6/72(57)]

का० प्रा० 2993.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 124-ग्रामतारी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कन्हैया लाल गोविन्दराम, गंगा भवन, रेसावपारा, ग्रामतारी, जिला रायपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बन्धेरा नाथ राविवराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. म.प्र.वि.सं./124/72(55)]

S. O. 2993.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kanhaiyalal Govindram, Ganga Bhawan, Ressaipara, Dhamtari, District Raipur who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 124-Dhamtari constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kanhaiyalal Govindram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/124/72(55)]

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1974

कां. प्र. 2994.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए असम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 58-गोहाटी पूर्व सभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जितेन्द्र चन्द्र हज़ारिका, हज़ारिका भवन, कालीचरन सेन रोड, पलटन बाजार, गोहाटी-8 (असम), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा सखीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जितेन्द्र चन्द्र हज़ारिका को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. असम वि. सं./58/72]

New Delhi, the 22nd October, 1974

S. O. 2994.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jitendra Chandra Hazarika, Hazarika Bhawan, Kalicharan Sen Road, Paltan Bazar, Gauhati—8 (Assam) a contesting candidate for general election to the Assam Legislative Assembly held in March, 1972 from 58-Gauhati East

constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jitendra Chandra Hazarika to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AS-LA/58/72]

कां. प्र. 2995.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए असम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 74-उदालगुरी (प्र.ज.ज.अ.) सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहन चन्द्र मेक, ग्राम गेरेकी बस्ती पो. तेजपुर, जिला दारंग, असम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा सखीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मोहन चन्द्र मेक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. असम-वि सं./74/72]

ए. एन. सेन, सचिव

S. O. 2995.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohan Chandra Mech, Village Gereki Basti, P.O. Tezpur, District Darrang, Assam, a contesting candidate for General election to the Assam Legislative Assembly held in March, 1972 from 74-Udalguri (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohan Chandra Mech to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AS-LA/74/72]

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1974

का० आ० 2996.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि मार्च, 1972 से हुये राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन से लिये 54-विजारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्योदयाल पुत्र रामप्रसाद सैन, ग्राम भटकोल, पी० मोथुका, तहसील किशनगढ़ बाग, जिला अलवर (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्धन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पन्न सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यापारिक नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री श्योदयाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निर्वाचित घोषित करना है ।

[स० राज०-वि० स०/54/72(44)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th October, 1974

S. O. 2996.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheo Dayal, S/o Shri Ram Prasad Sen, Village Bhatkol, P.O. Mothuka, Tehsil Kishanagarh—Bas, District Alwar, Rajasthan, a contesting candidate for General election to the Rajasthan Legislative Assembly held in March, 1972 from 54-Tijara constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheo Dayal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/54/72(44)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्यालय

(न्याय विभाग)

नोटिस

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1974

का० आ० 2997.— इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री ब्रह्मा नन्द नागपाल, एडवाकेट जी०-28/5 ए, राजोरी गार्डन, न्यू देहली-27 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, ओल्ड कोर्टम, रिटज बिल्डिंग के पीछे काश्मीरी गेट, देहली में लेख्य प्रमाणक (नोटरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति के लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशन होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें ।

[सं० एक० 22/31/73-न्याय]

क० त्याग राजन, सक्षम प्राधिकारी तथा उप-सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 28th October, 1974

S. O. 2997.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Brahma Nand Nagpal, Advocate, G, 28/5-A, Rajouri Garden, New Delhi-27 for appointment as a Notary to practice in the Old Courts, Behind Ritz Cinema, Kashmiri Gate, Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/31/73-JUS]

K. THYAGARAJAN, Competent Authority
and Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1974

का० आ० 2998.— सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेइखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के अवर सचिव (विधि) को, सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में उक्त प्रशासन के व्ययन के अधीन सरकारी स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

[स० यू० 14016/2/74-ए० पी०]

जी० के० मनोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th October, 1974

S.O. 2998.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the Under Secretary (Law) of the Administration of the Union Territory of Arunachal Pradesh, being a gazetted officer of the Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act, in respect of the public premises under the disposal of the said Administration in the States of Assam, Meghalaya and in the Union Territory of Arunachal Pradesh

[No. U. 14016/2/74-AP]

G. K. BHANOT, Joint Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1974

क्रा० आ० 2999.—घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये, केन्द्रीय सरकार, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदनाम सहित मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त करती है :

सारणी		
क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पदनाम
1	2	3
1	श्री पी० सी० शर्मा	मूल्यांकन अधिकारी

[सं 79/74/क्रा० सं 328/201/74-घ०क०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

ORDER

New Delhi, the 21st September, 1974

S. O. 2999.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the W.T. Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officer with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

TABLE

S. No.	Name of the person	Designation
1	2	3
1.	Shri P.C. Sharma	Valuation Officer

[No. 79/74/F. No 328/201/74-W.T.]

प्रादेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1974

क्रा० आ० 3000.—घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12 क के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों का मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है अर्थात्—

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम
1.	श्री० एम० बाजपेई
2.	के० क० शुक्ला
3.	पी० एन० पाठक
4.	ए० एस० त्रिपाठी

[सं 80/74/क्रा० सं 328/208/74-घन कर (शेयर)]

वी० डी० बाखरकर, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th September, 1974

S. O. 3000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. No.	Name of the person
1.	O. S. Bajpai
2.	K. K. Shukla.
3.	P. N. Pathak.
4.	A. S. Tripathi.

[No. 80/74/F. N. 328/208/74-WT (SHARES)]

V. D. WAKHARKAR, Under Secy.

(वैकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1974

क्रा० आ० 3001.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की निम्नलिखित पर, पत्रद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध धनलक्ष्मी बैंक लि०, त्रिवार द्वारा पाठनकुलम गांधी, तानुपदन डाकघराना, चण्डीगढ़ के निकट, त्रिवार जिला में धन अवन परिपक्वता (6.02 एकड़ जमीन) के सम्बन्ध में उक्त बैंक पर 4 अक्टूबर, 1975 तक लागू नहीं होंगे।

[सं 15(31)बी० आ० III/73]

(Department of Banking)

New Delhi, the 26th October, 1974

S. O. 3001.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of

the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Dhanalakshmi Bank Ltd., Trichur, in respect of the immovable property (6.02 acres of land) held by it at Pynkulam Village, Thozhupadam, P.O. near Chelakkara, Trichur District, till the 4th October, 1975.

[No. 15(34)-B.O. III/73]

का० प्रा० 3002.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता पर वही तक लागू नहीं होंगे अर्थात् तक कि उनका सम्बन्ध उक्त बैंक द्वारा यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि०, कलकत्ता के अंशों के धारण से है।

[सं० 15(20)बी० ओ० III/74]

मे० भा० उमगायकर, अवसर सचिव

S. O. 3002.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of The Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to United Bank of India, Calcutta, for a period of one year from the date of this notification, in so far as they relate to its holding shares in the United Industrial Bank Ltd., Calcutta.

[No. 15(20)-B.O. III/74]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1974

का० प्रा० 3003.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्ध 1 मार्च, 1971 से 28 फरवरी, 1975 तक की अवधि के लिये डिब्रूगढ़ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, डिब्रूगढ़ पर लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 8-5/71-77 सी०]

क० भवानी, अवसर सचिव

New Delhi, the 31st October, 1974

S. O. 3003.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act shall not apply to the Dibrugarh Central Co-operative Bank Ltd., Dibrugarh for the period from the 1st March, 1974 to 28th February, 1975

[No. F. 8-5/74-AC]

K. BAVANI, Under Secy

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

का० प्रा० 3004.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसूचन में अक्टूबर, 1974 की 25 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए

लेखा हणू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	प्राप्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	42,14,60,000		सोने का मिश्रण और बुलियन —		
			(क) भारत में रखा हुआ	1,82,52,68,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
संचालन में नोट	5957,41,45,000		विवेशी प्रतिभूतियां	1,41,73,97,000	
जारी किये गए कुल नोट		5999,56,05,000	जोड़		3,24,26,65,000
			रुपये का मिश्रण		19,93,83,0000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5655,35,57,000
			देशी विनियम बिल और दूसरे		
			वाणिज्य-पत्र		
कुल देयताएं		5999,56,05,000	कुल प्राप्तियां		5999,56,05,000

25 अक्टूबर 1974 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यालय का विवरण

देयताएं	रुपये	प्राप्तियां	रुपये
चुफता पूंजी	5,00,00,000	नोट	42,14,60,000
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,65,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	3,81,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	284,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	108,09,76,000
(स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	654,61,50,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	459,25,51,000
जमा राशियां—		निवेश**	324,74,71,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम:—	
(i) केन्द्रीय सरकार	57,16,99,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	9,02,18,000	(ii) राज्य सरकारों को/से	94,35,78,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	615,05,01,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	63,33,20,000
(ii) अनुसूचित राज्य		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को†	270,86,46,000
सहकारी बैंक	15,12,49,000	(iii) दूसरों को	7,14,50,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
सहकारी बैंक	1,47,19,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
(iv) अन्य बैंक	99,95,000	(क) ऋण और अग्रिम:—	
		(i) राज्य सरकारों को	67,82,39,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	14,63,10,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	63,80,00,000
(ग) अन्य	368,09,27,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,16,98,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और	
देय बिल	102,79,85,000	अग्रिम	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	47,59,06,000
अन्य देयताएं	583,85,08,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	
		से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	226,19,13,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांधों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य प्राप्तियां	96,74,87,000
रुपये	2552,58,01,000	रुपये	2552,58,01,000

*नकदी, धातविक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

(†) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों का किये गये अस्थायी घोषणापत्र शामिल हैं।

† रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सीमावी बिलों पर अग्रिम किये गये 21,82,00,000 रुपये शामिल हैं।

‡ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

Now Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3004.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 25th day of October, 1974
Issue Department

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	42,14,60,000		Gold Coin and Bullion:-		
Notes in circulation	5957,41,45,000		(a) Held in India	182,52,68,000	
Total Notes issued		5999,56,05,000	(b) Held outside India		
			Foreign Securities	141,73,97,000	
			Total		324,26,65,000
			Rupee Coin		19,93,83,000
			Government of India Rupee Securities		5655,35,57,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		
Total Liabilities		5999,56,05,000	Total Assets		5999,56,05,000

S. JAGANNATHAN, Governor.

Dated the 31st day of October, 1974.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 25th October, 1974.

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	42,14,60,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	2,65,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	Small Coin	3,81,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:-	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(a) Internal	108,09,76,000
Deposits:-		(b) External	
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	654,61,50,000
(i) Central Government	57,16,99,000	Baances Held Abroad*	459,25,51,000
(ii) State Governments	9,02,18,000	Investments**	324,74,71,000
(b) Banks		Loans and Advances to:-	
(i) Scheduled Commercial Banks	615,05,01,000	(i) Central Government	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	15,12,49,000	(ii) State Governments@	94,35,78,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,47,19,000	Loans and Advances to:-	
(iv) Other Banks	99,95,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	63,33,20,000
		(ii) State Co-operative Banks‡	270,86,46,000
		(iii) Others	7,14,50,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to:-	
		(i) State Governments	67,82,39,000
		(ii) State-Co-operative Banks	14,63,10,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	63,80,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,16,98,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		(c) Others	47,59,06,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
Bills Payable	102,79,85,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	226,19,13,000
Other Liabilities	583,85,08,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	96,74,87,000
RUPEES	2552,58,01,000	RUPEES	2552,58,01,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 21,82,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

S. JAGANNATHAN Governor.

[No. F. 10(1)/74-B.O.I.]

Dated the 31st day of October, 1974.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1974

क्र०प्र० 3005.—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अक्टूबर 1974 की 18 तारीख को समाप्त हुए गवताह के लिए खेबा (हशू विभाग)

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	31,38,48,000		सोने का सिक्का और वुलियन:—		
संचालन में नोट	60,07,64,10,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,68,000	
जारी किये गए कुल नोट		6039,02,58,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
			विदेशी प्रतिभूतियां	141,73,97,000	
			जोड़		324,26,65,000
			रुपये का सिक्का		19,40,78,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5695,35,15,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताएं		6039,02,58,000	कुल आस्तियां		6039,02,58,000

तारीख 23, अक्टूबर, 1974

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

18 अक्टूबर, 1974 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	31,38,48,000
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	5,00,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	284,00,00,000	छोटा सिक्का	
राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	खरीदे गये और भुनाये गये बिल	3,54,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000	(क) देशी	116,96,50,00
जमा राशियां:—		(ख) विदेशी	
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	868,90,95,000
(i) केन्द्रीय सरकार	121,80,92,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	450,34,59,000
(ii) राज्य सरकारें	5,95,50,000	निवेश**	134,41,60,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	567,95,71,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	14,83,59,000	(ii) राज्य सरकारों को†	95,61,63,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,56,82,000	ऋण और अग्रिम:—	
(iv) अन्य बैंक	1,19,41,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	67,57,50,00,000
(ग) अन्य		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को ††	265,33,68,000
वेय बिल	364,80,54,000	(iii) दूसरों को	4,64,50,000
	113,04,47,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
अन्य देयताएं	571,13,39,000	(क) ऋण और अग्रिम	
		(i) राज्य सरकारों को	67,82,39,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	14,68,90,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	63,80,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	11,16,98,000
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	47,61,08,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	223,60,27,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
रुपये	2561,10,35,000	रुपये अन्य आस्तियां	97,12,78,000
			2561,10,35,000

* नकदी आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं; परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी भोवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†† रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सीमावर्ती बिलों पर अग्रिम दिये गये 20,55,00,000 रुपये शामिल हैं।

††† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख 23 अक्टूबर, 1974

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

[सं० फ० 10(1)/74-बी०पी० 1]

च० ब० मीरखन्दानी, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1974

S O. 3005.—An Account pursuant to the Reserve Bank Of India Act, 1934, for the week ended the 18th day of October, 1974

(Issue Department)					
Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	31,38,48,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	6007,64,10,000		(a) Held in India	182,52,68,000	
			(b) Held outside India	
Total Notes issued		6039,02,58,000	Foreign Securities	14,73,97,000	
			Total		324,26,65,000
			Rupee Coin		19,40,78,000
			Government of India Rupee Securities		5695,35,15,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper
Total Liabilities		6039,02,58,000	Total Assets		6039,02,58,000

S. JAGANNATHAN, Governor

Dated the 23rd day of October, 1974

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 18th October, 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	31,38,48,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	5,00,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	Small Coin	3,54,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(a) Internal	116,96,50,000
Deposits :—		(b) External	
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	868,90,95,000
(i) Central Government	121,80,92,000	Balances Held Abroad*	450,34,59,000
(ii) State Governments	5,95,50,000	Investments**	134,41,60,000
(b) Banks		Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	567,95,71,000	(i) Central Government	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	14,83,59,000	(ii) State Governments@	95,61,63,000
(iii) Non-Schedule 1 State Co-operative Banks	1,56,82,000	Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks	1,19,41,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	67,57,50,000
(c) Others	364,60,54,000	(ii) State Co-operative Banks††	265,33,68,000
Bills Payable	113,04,47,000	(iii) Others	4,64,50,000
Others Liabilities	571,13,39,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
Rupees	2561,10,35,000	(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments	67,82,39,000
		(ii) State Co-operative Banks	14,68,90,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	63,80,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,16,98,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	47,61,08,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	223,60,27,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	97,12,76,000
		Rupees	2561,10,35,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 20,55,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

S. JAGANNATHAN, Governor.

Dated the 23rd day of October, 1974.

[No. F. 10(1)/74-B.O-I]

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 3rd September, 1974.

S.O. 3006.—In pursuance of clause (3) of Article 77 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 10 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1958, (hereinafter referred to as the said rules) in sub-rule (2-A), for the portion beginning with the words, "The Administrator" and ending with the words "mentioned in that order", the following shall be substituted, namely:—

"The Administrator or Head of a Department may, by order, authorise a Gazetted Officer serving under him to exercise to such extent as may be specified in that order, any of the powers conferred on such Administrator or Head of the Department under sub-rule (1) or sub-rule (2)".

3. In the proviso to rule 14 of the said rules, after the words "may not be referred", the words "by the Ministries/ Departments of the Central Government, shall be inserted.

4. For Schedule I to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE I

List of Head of Departments as on 31st October, 1973

[See rule 2(e)]

I—MINISTRY OF AGRICULTURE

A. Department of Agriculture:

1. Plant Protection Adviser, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, New Delhi.
2. Economic and Statistical Adviser, Directorate of Economic and Statistics, New Delhi.
3. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad.
4. Director of Administration, Directorate of Extension Training, New Delhi.
5. Chief Engineer, Central Groundwater Board, Faridabad.
6. Chairman, Delhi Milk Scheme, New Delhi.
7. President, Forest Research Institute and College, Dehradun.
8. Director, Tractor, Training and Testing Station, Budni.
9. Member Secretary, Agricultural Prices Commission.
10. Chief Co-ordinator of Projects, Pre-investment Surveys of Forest Resources, New Delhi.
11. Inspector General of Forests and Ex-officio Director of the Project Logging Training Centres.
12. Director, Tractor Training Centre, Hissar.
13. Member-Secretary of the National Commission of Agriculture, New Delhi.
14. Director, Pre-investment Survey of Fishing Harbour Project, Bangalore.
15. Director, Tractor Training Centre, Mysore.
16. Chairman, Agriculture Price Commission, New Delhi.

17. Superintending Engineer, Deep Sea Fishing Station, Bombay.

18. Director, Central Institute of Fisheries Education, Bombay.

19. Director, Central Institute of Fisheries Operations, Cochin.

20. Director, Integrated Fisheries Project, Cochin.

21. Director of Agricultural Aviation.

B. Department of Food:

1. Chief Director, Directorate of Sugar and Vanaspati, New Delhi.

2. Director, National Sugar Institute, Kanpur.

II—CABINET SECRETARIAT

A. Department of Personnel:

1. Director, Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussorie.
2. Director, Central Bureau of Investigation.
3. Director, Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.
4. Central Vigilance Commissioner.
5. Director, Enforcement.
6. Director of Revenue Intelligence, New Delhi.

III—MINISTRY OF COMMERCE

Department of Foreign Trade:

1. Director General, Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.
2. Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.
3. Textile Commissioner, Bombay.
4. Jute Commissioner, Calcutta.
5. Chairman Tariff Commission, Bombay.
6. Custodian of Enemy Firms, Bombay.
7. Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone.
8. Development Commissioner for Handicrafts.

IV—MINISTRY OF COMMUNICATIONS

1. Director General, Overseas Communications Service.
2. Wireless Adviser to the Government of India.

V—MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

A. Department of Culture:

1. Director General, Archaeological Survey of India.
2. Librarian, National Library, Calcutta.
3. Director, National Museum, New Delhi.

B. Department of Education:

1. Director, National Archives of India, New Delhi.
2. Director of Central Hindi Directorate, New Delhi.
3. Director, Asian Institute of Educational Planning and Administration, Delhi.
4. Director Anthropological Survey of India, Calcutta.
5. Chairman, Standing Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi.

6. Director, Directorate of Adult Education, New Delhi.

VI—MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

Chief Pass-port Officer.

VII—MINISTRY OF FINANCE

A. Department of Expenditure :

Controller General of Defence Accounts.

B. Department of Revenue and Insurance:

1. Central Board of Excise and Customs.
2. Central Board of Direct Taxes.
3. Commissioners of Income Tax.
4. Collectors of Customs Bombay, Calcutta and Madras.
5. Collectors of Central Excise, Allahabad, Bangalore, Baroda, Bombay, Calcutta and Orissa, Delhi, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, Patna, Poona, Shillong and West Bengal.
6. Narcotics Commissioner.
7. Director of Inspection (Income Tax).
8. Director of Inspection (Customs and Central Excise).
9. Director of Inspection (Investigation).
10. Director Inspection (Research Statistics and Publication).
11. Collector of Customs and Central Excise, Cochin.
12. Collector of Customs and Central Excise, Goa.
13. Gold Control Administrator. Regional Office of the Gold Control Administration, Bombay.
14. Chief Chemist, Central Revenues Control Laboratory, New Delhi.
15. Director, Emergency Risks Insurance Schemes, New Delhi.
16. Collector, Central Excise, Chandigarh.
17. Additional Commissioners of Income Tax.
18. Collectors of Customs (Preventive), Bombay.
19. Collectors of Central Excise, Ahmedabad, Guntur and Madurai.
20. Controller of Insurance, Simla.
21. Director of Training I.R.S. (Direct Taxes) Staff College, Nagpur.

C. Department of Economic Affairs:

1. National Savings Commissioner for India.
2. Master, India Government Mint, Alipore, Calcutta.
3. Master, India Government Mint, Bombay.
4. General Manager, and Ex-officio Controller of stamps Nasik Road, in respect of India Security Press, Nasik Road (Including the Stamp Press, Currency note Presses and Central Stamp Stores).
5. General Manager, Silver Refinery, Calcutta.
6. General Manager, Security Paper Mills Project Hoshangabad.
7. Master, India Government Mint, Hyderabad.
8. Officer on Special Duty, Intaglio Press.

D. Department of Banking:

Administrator, Rehabilitation Finance Administration Unit, New Delhi.

VIII—MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

Department of Health:

Director General, Health Services.

IX—MINISTRY OF HOME AFFAIRS

1. Director, Intelligence Bureau.
2. Director, National Commandant, Central Police Academy, Mount Abu.
3. Registrar—General and Ex-Officio Census Commissioner for India.
4. Director General, Central Reserve Police.
5. Commissioner for Linguistic Minorities, Allahabad.
6. Director of Co-ordination (Police Wireless) New Delhi.
7. Director General, Directorate General of Civil Defence.
8. Joint Director, Intelligence Bureau and ex-officio Special Inspector-General of Police Indo-Tibetan Border Police, New Delhi.
9. Inspector General of Assam Rifles.
10. Director General, Border Security Force.
11. Sector Commanders of the Border Security Force.
12. Inspectors General, Central Reserve Police Sectors I, II and III.
13. Inspector-General, Central Industrial Security Force.
14. Director, Bureau of Police Research and Development.
15. Director, Central Translation Bureau, New Delhi.
16. Director General, Backward Classes Welfare.
17. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, India.

X—MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Department of Industrial Development:

1. Director General Technical Development.
2. Chief Inspector of Explosives India.
3. Controller General of Patents Designs and Trade Marks.
4. Development Commissioner, Small Scale Industries.
5. Salt Commissioner.
6. Economic Adviser to the Government of India.
7. Director General, Research and Development Organisation for Electrical Industry, Bhopal.
8. Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices.

XI—MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

1. Chairman, Central Water and Power Commission.
2. General Manager, Farackka Barrage Project.
3. Chairman, Central Electricity Authority.
4. Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Farakka Barrage Project.

XII—MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

1. Director General, All India Radio.
2. Principal Information Officer, Press Information Bureau.

- 3 Controller-cum Chief Producer, Films Division, Bombay
- 4 Director, Publications Division, Delhi
- 5 Director of Advertising and Visual Publicity
- 6 Director of Field Publicity
- 7 Registrar of News Papers for India
- 8 Director Song and Drama Division
- 9 Chairman, Central Board of Film Censors, Bombay-6
- 10 Director, Film and Television Institute of India, Poona

XIII—MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

A Department of Rehabilitation

- 1 Chief Administrator, Dandakanya Project
- 2 Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Dandakanya Project
- 3 Chief Settlement Commissioner of Employment and Training
- 4 Chief Pay and Accounts Officer (Rehabilitation)
- 5 Chief Development cum Rehabilitation Commissioner
- 6 Chief Commandant Mana Group of Transit Centres, Mana., Raipur (M P)
- 7 Chief Mechanical Engineer Rehabilitation, Jeypore, District Koriaput (Orissa)

B Department of Labour and Employment

- 1 Director of Employment Exchanges, Directorate General
- 2 Director of Training
 - (i) Directorate General of Employment and Training (in respect of the Central Training Institutes) Calcutta Madras/Bihar/Hyderabad/Ludhiana/Kanpur and New Delhi
 - (ii) Central Staff Training and Research Institute, Calcutta
 - (iii) Advanced Training Institute, Madras
 - (iv) Foreman, Training Institute, Bangalore (under his control)
- 3 Chief Labour Commissioner, New Delhi (Central).
- 4 Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes
- 5 Director, Labour Bureau, Simla
- 6 Director General of Mines Safety, Dhanbad.
- 7 Coal Mines Welfare Commissioner, Dhanbad
- 8 Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare Fund Dhanbad
- 9 Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for Rajasthan in respect of the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation in Rajasthan.
- 10 Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for Andhra in respect of the Office of the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation in Andhra Pradesh
- 11 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh in respect of the Office of the Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Andhra Pradesh
- 12 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the

State of Bihar in respect of the Office of the Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for Bihar

13 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the State of Orissa in respect of the Office of the Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee, Orissa

14 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the State of Madhya Pradesh in respect of the Office of the Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for Madhya Pradesh

15 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for Goa, Daman and Diu in respect of the Office of the Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for Goa, Daman and Diu

16 Director of Employment Exchanges, Directorate General of Employment and Training in respect of Labour Depot, Gorakhpur

17 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the State of Mysore in respect of the Office of the Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee, Mysore

18 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the State of Maharashtra in respect of the Office of the Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee, Maharashtra

19 Director of Employment Exchanges, Directorate General of Employment and Training in respect of the following offices —

- (i) Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Kurla-Bombay-70/Hyderabad-7
- (ii) Office of the Employment Liaison Officer for Rehabilitation of East Pakistan Migrants, Mana-Camp, Raipur, Madhya Pradesh
- (iii) Office of the Officer on Special Duty, Special Cell, Farrakka Barrage Project, Calcutta (West Bengal)
- (iv) Office of the Sub-Regional Employment Officer Coaching-cum-Guidance Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Delhi/Kanpur (U P), Jabalpur (M P), Madras (Tamil Nadu)

20 Member-Secretary of the Expert Committee on Unemployment.

21 Director of Employment Exchange, Director General of Employment and Training in respect of the following office —

Central Institute for Research and Training in Employment Service, Pusa, New Delhi

XIV—MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

A Department of Legal Affairs

President, Income Tax Appellate Tribunal

B Legislative Department

Chief Selection Commissioner

C Department of Company Affairs

Chairman, Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.

XV(a).—MINISTRY OF PLANNING

Department of Statistics:

1. Director, Field Operations Division, National Sample Survey Organisation, New Delhi.
2. Director, Central Statistical Organisation, New Delhi.
3. Director, Computer Centre, New Delhi.
4. Director-in-Charge, Data Processing and Survey Design and Research Division.

XV(b).—MINISTRY OF STEEL AND MINES

A. Department of Steel :

Iron and Steel Controller, Calcutta.

B. Department of Mines :

1. Coal Controller, Calcutta.
2. Director General, Geological Survey of India, Calcutta.
3. Controller, Indian Bureau of Mines, Nagpur.
4. Chairman and Managing Director, Kolar Gold Mining Undertaking.

XVI.—DEPARTMENT OF SUPPLY

1. Director General Supplies and Disposals.
2. Chief Pay and Accounts Officer.
3. Director, National Test House, Calcutta.

XVII.—MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

1. Director General of Shipping, Bombay.
2. Director General of Light Houses and Light Ships.
3. Government Director on the Board of Directors of Indian Shipping Companies, Bombay.
4. Chairman, Inter-States Transport Commission.
5. Principal Officers, Mercantile Marine Department, Bombay, Calcutta and Madras.
6. Chief Engineer, Andaman, Laccadive Harbour, Works.
7. Chief Engineer-cum-Administrator of the Directorate of Inland Water Transport.
8. Chief Engineer and Administrator, Mangalore Harbour Project.
9. Chief Engineer and Administrator, Tuticorin Harbour Project.

XVIII.—DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. Surveyor General, Survey of India, Dehradun.
2. Director, Zoological Survey of India, Calcutta.
3. Director, Botanical Survey of India.
4. Director, National Atlas Organisation, Calcutta-19.

XIX.—MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

1. Director General of Civil Aviation.
2. Director General of Observatories.
3. Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
4. Additional Commissioner of Railway Safety, Western Circle, Bombay.

5. Additional Commissioner of Railway Safety, North Eastern Circle, Calcutta.

6. Additional Commissioner of Railway Safety, Northern Circle, Lucknow.

7. Chairman, Town and Country Planning Organisation, Circle, Bangalore.

8. Director General of Tourism.

XX.—MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

1. Engineer-in-Chief, Central Public Works Department.
2. Director of Printing.
3. Controller of Stationery.
4. Controller of Publications.
5. Director of Estates.
6. Director, National Building Organisation.
7. Chairman, Town and Country Planning Organisation.

XXI.—UNION TERRITORIES

(a) Delhi Administration :

Inspector-General of Police, Delhi State.

(b) Pondicherry Administration :

Chief Secretary, Pondicherry Administration.

(c) Andaman and Nicobar Islands Administration :

1. Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands.
2. Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration.
3. Development Commissioner-cum-Development Secretary, Andaman and Nicobar Administration.
4. Deputy Commissioner, Andaman and Nicobar Administration.
5. Principal Engineer, Andaman P.W.D.

(d) Chandigarh Administration :

1. Chief Engineer, Capital Project, Chandigarh.
2. Director, Post Graduate Institute, Chandigarh.
3. The Principal, Punjab Engineering College, Chandigarh.
4. Controller of Printing and Stationery, Chandigarh.
5. Professor, Punjab Engineering College, Chandigarh and ex-officio Director, Technical Education, Chandigarh.

(e) Dadra and Nagar Haveli Administration :

Collector of Dadra and Nagar Haveli.

(f) Goa, Daman and Diu :

1. Chief Secretary.
2. Director of Accounts.
3. Collector of Daman.
4. Development Commissioner.
5. Collector of Goa.
6. Secretary, Industries and Labour, Goa, Daman and Diu.
7. Judicial Commissioner.
8. Secretary to the Lt. Governor of Goa, Daman and Diu.
9. Chief Electrical Engineer, Goa.
10. Principal Engineer P.W.D. Goa, Daman and Diu.
11. Director of Education, Goa, Daman and Diu.

- (g) Arunachal Pradesh :
Chief Secretary.
- (h) Mizoram :
Chief Secretary.
- (i) North Eastern Council :
Secretary."

5. In the Annexure to Schedule V to the said rules, for item 16, the following item shall be substituted, namely :—

"16. Printing and Binding Full powers where the printing is executed through or with the approval of the Director of Printing.

1. The expenditure shall be incurred subject to the provisions of the rules for printing and binding and any other orders that the administrative Ministry of the Directorate of Printing may lay down from time to time. Normally, the entire printing and binding work is executed through the Director of Printing who will raise necessary debits against the budget head of account of the department concerned for the printing work done by him.

NOTE : Ordinarily a Government Press will not accept any order for printing of pamphlets, publications, booklets, reports, etc. if the number of copies required is less than 500. The requisite number of copies may be got cyclostyled by the Departments themselves. Printing at private presses may be resorted to only in exceptional cases. If desired, printed covers may be got made and the pamphlets etc., stapled or wire stitched and trimmed by local arrangements through private presses, if necessary. A Government Press will not accept any order for the printing of a Special Form if the number of copies required is less than 3,000 and in such cases, the Ministry/Department concerned should get the requisite copies cyclostyled or get them printed through private presses. In all these cases, the Ministries/Departments shall have full powers without any monetary limit for Printing/Binding, at private presses. Scrutiny of printers' bills and payment thereof shall be made direct by the Ministries/Departments themselves.

2. The following authorities may get their emergent and unforeseen petty printing and binding jobs executed locally through private agencies upto the monetary limits indicated against them, which shall include the cost of paper and other binding materials :—

- (i) Ministries Rs. 2,000 per annum.
- (ii) Heads of Departments Rs 1,000 per annum.
- (iii) Heads of Offices Rs 500 per annum.

The cost of printing and binding job executed through private agencies shall be debited against the Head of Expenditure on Printing and Publications. No approval of rates by the Director of Printing is necessary.

3. Where in respect of emergent and special cases the cost printing and binding executed locally through private agencies exceeds the monetary limit specified in paragraph 2 and the Ministry/Department of the Government of India considers it essential to get such jobs executed through private agencies, such Ministry/Department may, if the rates to be paid to such private agencies do not exceed those admissible under the Schedule of Rates maintained for the time being by the Director of Printing, get the jobs executed through such private agencies without obtaining the approval of the Director of Printing. The scrutiny of bills and payment to printers will be made direct by the Ministry/Department and the Director of Printing shall, if so required, render assistance in drawing up specifications and conditions of contract.

Provided that where it is proposed to entrust jobs to private agencies in excess of the rates specified in the Schedule of Rates referred to above, the Ministry/Department may decide each case in consultation with its associated Finance."

6. In Schedule VII to the said rules, in the Table.—

(a) in the entry "Deficiencies and Depreciation in the value of stores included in the stock on other accounts," after the words "value of stores", the brackets and words "(other than a motor vehicle or a motor cycle)" shall be inserted;

(b) after the entry as so amended, the following entry shall be inserted, namely :—

"Condemnation of Central motor vehicles and motor cycles Departments Rs. 25,000—This power may be exercised subject to the following restrictions, namely :—

(a) the lives of various types of vehicles, in terms of distance run (in kilometers) and length of use (in years) whichever is reached later, have been fixed as under :—

	Kilo-meters	Year
(i) Heavy Commercial motor vehicles.	2,00,000	10
(ii) Motor vehicles fitted with less than 18 H.P. (R.A.C.).	1,20,000	6
(iii) Motor cycles fitted with engines of 3.5 H.P. (R.A.C.) or above.	80,000	5

- Kilometers years
- (iv) Motor cycles 48,000 5
fitted with
engines of less
than 3.5 H.P.
(R.A.C.).
- (b) A vehicle in the Union territory of Delhi should be condemned only after a certificate has been obtained from the Electrical and Mechanical Officer, Civil Aviation Department through the Ministry of Tourism and Civil Aviation or the Delhi Transport Corporation through the Ministry of Shipping and Transport to the effect that the vehicle is not fit for any further economical use. At places outside the Union territory of Delhi, a certificate as aforesaid from a similar technical authority will be necessary for condemning a vehicle."

[No. F. 1(9)-E.II(A)/72]

G.S. RATHIE, Under Secy.

New Delhi, the 9th October, 1974

S.O. 3007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Fifth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, in sub-rule (4) of rule 12, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government, is subsequently absorbed in such body corporate with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber, the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-rule".

[No. F. 16(2)-E.V.(B)/72]

New Delhi, the 14th October, 1974

S.O. 3008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and of all other powers enabling him in this behalf the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Tenth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 34 of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of Office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed with a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of Office or Department for payment of the amount in the Fund. The application shall be made—

(A) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(B) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts Statement has not been received by the subscriber."

[No. 2(62)(i)-E.V.(B)/71-GPF]

V. K. PANDIT, Dy. Secy.

भाषिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1974

(इलायची नियंत्रण)

का० प्रा० 3009—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भारत सरकार श्री टी० बी० स्वामीनाथन के स्थान पर श्री के० बी० जार्ज, निदेशक, इलायची विकास इलायची बोर्ड, एन०कुलम को 14 जून, 1974 के आदेश से 24 जून 1974 के पूर्वार्द्ध तक, जिसमें यह भी शामिल है, इलायची बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इलायची बोर्ड, एन०कुलम के अध्यक्ष का पद एक सावधिक पद है, जिसमें काफी उम्मेदवारों का प्रत्यक्ष रूप से और इसे खाली नहीं रखा जा सकता। श्री टी० बी० स्वामीनाथन, अध्यक्ष, इलायची बोर्ड, एन०कुलम को तबायला करके केरल सरकार को वापस भेज दिया गया था और तदनुसार श्री के० बी० जार्ज, निदेशक, इलायची बोर्ड को अस्थायी व्यवस्था के रूप में श्री स्वामीनाथन से इलायची बोर्ड के अध्यक्ष के पद का कार्यभार सम्भालने के लिए तार द्वारा कहा गया था। श्री जार्ज ने 14-6-74 (अपराह्न) को अध्यक्ष पद का कार्यभार सम्भाल लिया। मंत्रालय को यह तारीख केवल 20-6-74 को कार्यभार रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मालूम हो सकी। यद्यपि इलायची बोर्ड के अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण करने की सही तारीख जाने बिना अधिसूचना पहले से जारी करना संभव न था। इसलिए उनके द्वारा किये गये सावधिक कार्यों को नियमित करने के लिए इस अधिसूचना को भूतवर्ती प्रभाव से लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस भूतवर्ती प्रभाव से इसको लागू करने से इलायची बोर्ड में किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 29(5)/74-ग्लॉट (बी)]

(Cardamom Control)

New Delhi, the 4th November, 1974

S.O. 3009.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3), read with sub-section (4) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), the Central Government appoints Shri K. V. George, Director of Cardamom Development, Cardamom Board, Ernakulam, as Chairman of the Cardamom Board for the period commencing from the afternoon of the 14th June, 1974 upto and inclusive of the forenoon of the 24th June, 1974, in place of Shri T. V. Swaminathan.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The post of Chairman, Cardamom Board, Ernakulam, is a statutory post involving considerable responsibilities and it cannot be kept vacant. Shri T. V. Swaminathan, the Chairman, Cardamom Board, Ernakulam, was transferred back to the Government of Kerala and accordingly Shri K. V. George, Director, Cardamom Board, was telegraphically asked to take over charge of the post of Chairman, Cardamom Board from Shri Swaminathan as a temporary arrangement. Shri George took over charge of the post of Chairman on 14-6-1974 (afternoon). This date was known to the Ministry only on receipt of the Charge Report on 20-6-1974. Thus it was not possible to issue the notification earlier without knowing the exact date of assumption of charge of the post of Chairman, Cardamom Board. There is, therefore, no alternative but to give effect to this notification retrospectively in order to regularise the statutory functions performed by him. It may also be stated that this giving of retrospective effect will not adversely affect anybody in the Cardamom Board.

[No. 29(5)/74-Plant(B).]

का० प्रा० 3010.—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भारत सरकार श्री के० वी० जार्ज के स्थान पर प्रोफेसर के० एम० चांदी, अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड, कोट्टायम को 24 जून, 1974 को पूर्वाह्न में उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त इलायची बोर्ड, एर्नाकुलम के अध्यक्ष के पद पर एतद्वारा नियुक्त करनी है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इलायची बोर्ड एर्नाकुलम के अध्यक्ष का पद एक सांविधिक पद है, जिसमें काफ़ी उत्तरदायित्व सम्मिलित है और इसे खाली नहीं रखा जा सकता।

श्री के० वी० जार्ज, निदेशक, इलायची बोर्ड की अस्थायी रूप में निदेशक के रूप में अपने कार्यभार के अतिरिक्त इलायची बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया था, बाद में यह विनिश्चय किया गया कि प्रोफेसर के० एम० चांदी, अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड, कोट्टायम को अध्यक्ष रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के रूप में अपने कार्यभार के अतिरिक्त श्री के० वी० जार्ज से इलायची बोर्ड के अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया और इस संबंध में तार द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गये थे। प्रोफेसर के० एम० चांदी द्वारा इस पद का कार्यभार संभालने की तारीख मंत्रालय को केवल 29 जून, 1974 को ज्ञात हुई। प्रोफेसर के० एम० चांदी द्वारा इलायची बोर्ड के अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण की तारीख पता न होने से, अधिसूचना पहले जारी न की

जा सकी। अतः प्रोफेसर के० एम० चांदी द्वारा इलायची बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से किये गये कार्यों को नियमित करने के लिए इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि भूतलक्षी प्रभाव से इसे लागू करने से इलायची बोर्ड में किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 29(5)/74-प्लांट(बी)]

एम० महादेव अय्यर, अवर सचिव

S.O. 3010.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3), read with sub-section (4), of section 4 of the Cardamom Act, 1965, (42 of 1965), the Central Government hereby appoints Prof. K. M. Chandy, Chairman, Rubber Board Kottayam, as chairman of the Cardamom Board, Ernakulam, in addition to his own duties as Chairman, Rubber Board, with effect from the forenoon of the 24th June, 1974, in place of Shri K. V. George.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The post of Chairman, Cardamom Board, Ernakulam is a statutory post involving considerable responsibilities and it cannot be kept vacant.

As Shri K. V. George, Director, Cardamom Board, was requested as a temporary measure to take charge of the post of Chairman, Cardamom Board, in addition to his own duties as Director, it was later decided that Prof. K. M. Chandy, Chairman, Rubber Board, Kottayam should be asked to take over charge of the post of Chairman Cardamom Board, in addition to his own duties as Chairman, Rubber Board, Kottayam, from Shri K. V. George and necessary telegraphic instructions were issued to this effect. The date of taking over charge of this post by Prof. K. M. Chandy became known to the Ministry only on 29th June, 1974. In the absence of the date of assumption of charge of the post of Chairman, Cardamom Board, Ernakulam by Prof. K. M. Chandy, the notification could not be issued earlier. There is, therefore, no other alternative but to give this notification retrospective effect in order to regularise the statutory functions performed by Prof. K. M. Chandy as Chairman of the Cardamom Board from the date of assumption of charge of the post. It may also be stated that this giving of retrospective effect will not adversely affect anybody in the Cardamom Board.

[No. 29(5)/74-Plant(B)]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

संयुक्त-मुद्रा नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1974

आदेश

का०प्रा० 3011.—सर्वश्री चावला एंड कं० 9986, बलदेव भटन, सराय गिल्सा न्यू रोडतक रोड, नई दिल्ली को सामान्य क्षेत्र से ग्रन्टा हाई मोलिब्डमर बेट हाई डेन्सिटी मोलिब्डम पाउडर आदि के आयात के लिए 5000/-रु० का आयात लाइसेंस संख्या: पी/एम/1803457/सी, दिनांक 7-12-73 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुमति सीमाशुल्क कार्य संबंधी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उस की मूल प्रतियां बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

2. उपर्युक्त विवरण के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैडबुक 1973-74 की संख्या कंडिका 330 के अंतर्गत तथा अपेक्षित एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल प्रतियाँ खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

3. आयात नियंत्रण आदेश 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सीसी) के अंतर्गत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं उक्त लाइसेंस की दोनों प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

4. अब आवेदक को आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैडबुक 1973-74, की कंडिका 320 की व्यवस्था के अनुसार उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियाँ जारी की जा रही हैं।

[एफ संख्या एन०पी०/सी० 9/एएम०-74/एयू०यूटी०/सी०एल०ए०3819]

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

ORDERS

New Delhi, the 23rd March, 1974

S.O. 3011.—M/s. Chawla & Co. 9986, Baldeo Bhawan, Sarai Rohilla, New Rohtak Road, New Delhi were granted the import licence No. P/S/1803458/C, dated 7-12-1973 for Rs. 5000 for Ultra High Molecular Weight High Density Moulding Powder etc. from G.A. They have applied for issue of DUPLICATE CUSTOM & EXCHANGE CONTROL COPIES of the said licence on the ground that the original thereof have been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. The applicant has filed an affidavit in support of the above statement, as required under Para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74. I am satisfied that the original copies of the said licence have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955, I order the cancellation of the both copies of the said licence.

4. The applicant is now being issued DUPLICATE CUSTOM & EXCHANGE CONTROL COPIES of the aforesaid licence in accordance with the provision of Para 320 of the I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

[F. No. NP/C-9/AM.74/AU.UT/CLA/5819]

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1974

क्रा०प्रा० 3012—सर्वश्री चावला एंड कं०, 9986, बलदेव भवन, सराय रोहिल्ला, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली को वास्तविक उपयोगिता श्रेणी के अंतर्गत पोलिथिलीन प्रोपलीन को-मोलिमर आदि के आयात के लिए लाइसेंस संख्या : पी/एम/1803390/सी एवं पी/एम/1803391/सी, दिनों का दिनांक 1-12-73 स्वीकृत किए गए थे।

उन्होंने उक्त लाइसेंसों की अनुलिपि प्रति (दोनों प्रतियों) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि इसकी मूल प्रतियाँ खिलकुल उपयोग किए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

उक्त विवरण के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैडबुक, 1973-74 की कंडिका 320 के अंतर्गत

यथा अपेक्षित एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंसों की मूल प्रतियाँ खो गई / अस्थानस्थ हो गई हैं।

आयात नियंत्रण आदेश, 1955, दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सी सी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं लाइसेंसों की उक्त प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैडबुक, 1973-74 की कंडिका 320(4) की व्यवस्था के अनुसार उक्त लाइसेंसों की अनुलिपि प्रतियाँ जारी की जा रही हैं।

[एफ०सं०एनपीसी-7/ए०एम०-74/एयू०यूटी०/सीएलए/1744]

New Delhi, the 17th July, 1974.

S.O. 3012.—M/s. Chawla & Co. 9986, Baldeo Bhawan, Sarai Rohilla, New Rohtak Road, New Delhi were granted licence Nos. P/S/1803390/C and P/S/1803391/C both dated 1-12-1973 under Actual Use Category for import of Ethylene Propylene co-polymer etc.

They have applied for the issue of DUPLICATE (BOTH COPIES) of above LICENCES on the ground that the original copies thereof have been lost/misplaced without having been utilised at all.

The applicants have filed affidavit in support of the above statement, as required under Para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & procedure, 1973-74. I am satisfied that the original copies of the said licences have been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me, under Section 9(cc) of Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955, I order the cancellation of the said copies of the licences.

The applicants are now being issued DUPLICATE COPIES of above licences in accordance with the provision of Para 320(4) of the I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

[F. No. NP/C-7/A.M. 74/AU. UT/CLA/1744]

क्रा०प्रा० 3013.—सर्वश्री चावला एंड कं०, 9986, बलदेव भवन, सराय रोहिल्ला, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली को वास्तविक उपयोगिता श्रेणी के अंतर्गत पी०टी०एफ०ई० रेजिन के आयात के लिए लाइसेंस संख्या : पी/एम/1801547 एवं 1801548 दोनों का दिनांक 12-7-73 है, स्वीकृत किए गए थे।

उन्होंने उक्त दोनों लाइसेंसों की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनकी मूल प्रतियाँ का पूर्ण उपयोग करने के बाद खो गईं/अस्थानस्थ हो गईं।

आवेदकों ने उपर्युक्त विवरण के समर्थन में आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैडबुक, 1973-74 की कंडिका 320 के अंतर्गत यथा अपेक्षित शपथपत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंसों की प्रतियाँ खो गईं/अस्थानस्थ हो गई हैं।

आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं लाइसेंसों की उक्त प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

आवेदकों को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हंडबुक, 1973-74 की कंडिका 320(4) की व्यवस्था के अनुसार उक्त दोनों लाइसेंसों की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियां जारी की जा रही हैं।

[एफ० संख्या एन सी/सी-2/ए एम-74/एयू-यूटी/सी एल ए/1707]

के० आर० धीर, उप मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

S.O. 3013.—M/s. Chawla & Co. 986, Baldeo Bhavan, Sarai Rohilla, New Rohtak Road, New Delhi were granted licence Nos. P/S/1801547 and 1801548 both dated 12-7-73 under Actual User Category for import of P.T.F.E. Resins.

They have applied for the issue of DUPLICATE EXCHANGE CONTROL COPIES OF BOTH THE LICENCES on the ground that the original copies thereof have been lost/misplaced having been fully utilised.

The applicants have filed affidavit in support of the above statement, as required under Para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74, I am satisfied that the original copies of the said licences have been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me, under Section 9(cc) of import Control Order, 1955 dated 7-12-1955. I order the cancellation of the said copies of the licences.

The applicants are now being issued DUPLICATE COPIES (EXCHANGE CONTROL COPIES OF BOTH LICENCES) in accordance with the provision of Para 320(4) of the I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

[No. NP/C-2/AM. 74/AU. UT/CLA/1707]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

समाहर्ता कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

गुन्टूर, 18 जून, 1974

क्रा० प्रा० 3014.—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के अन्तर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उन सभी अधिकारियों को जो सहायक समाहर्ता में नीचे के पत्र के नहीं हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन स्तम्भ 4 में निर्दिष्टित सीमाओं तक, समाहर्ता की शक्ति के प्रयोग का प्राधिकार प्रदान करता हूँ।

क्रम सं०	के० उत्पाद शुल्क नियम संख्या	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधि-कारी का पद	सीमाएं यदि कोई हों
1	2	3	4

- नियम 173 जी०(1) सहायक समाहर्ता तथा उनसे की भवावगी) निर्धारित की जा रही है।

1	2	3	4
			का उपयोग करने) पर हम सुविधा का प्रयोग करने से वंचित कर दिया है या तत्पश्चात् उसे पुनः हमका प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है, अन्यथा सहायक समाहर्ता या उससे ऊंचे पद वाले अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

- नियम 9 सहायक समाहर्ता तथा उनसे ऊंचे पद के अधिकारी।

टिप्पणी — 1. इस संबंध में सहायक समाहर्ता द्वारा अनुमति प्रदान की जानी चाहिए किन्तु प्रत्येक स्थिति में उन्हें इसकी सूचना समाहर्ता तथा मुख्य लेखा अधिकारी को देनी होगी।

- सहायक समाहर्ता बैंक द्वारा शुल्क भरा करने की अनुमति नहीं देते तो ऐसी व्यवस्था में निर्धारित है इसके विरुद्ध समाहर्ता के समक्ष जो कि अपोलीय प्राधिकारी भी है, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

- इस समाहर्ता कार्यालय की बिनाक 4-6-71 की अधिसूचना सं० 1/71 की क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ 4 में की गई प्रविष्टि उपरोक्त सीमा तक संशोधित की जाती है।

[अधिसूचना सं०-2/74 के० उत्पाद —फा० सी० सं०—IV/8/1/74-एम०

पी०-2 से जारी की गई]
ए० एस० भार्गव जाकर, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Guntur, 18th June, 1974

S.O. 3014.—In exercise of the powers conferred upon me under rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I authorise all Officers not below the rank of Assistant Collectors to exercise within their respective jurisdictions the power of Collector under Central Excise rules mentioned in Column 2 of the table subject to the restriction mentioned in Column 4 thereof.

Sl. No.	Central Excise Rule No.	Rank of the Central Excise Officer	Restrictions, if any
1	2	3	4
1.	Rule 173G(1) (Payment of duty by Cheques).	All Officers of and above the rank of Asstt. Collector.	Payment of duty by cheque may be permitted by officers of and above the rank of Asstt. Collector except where the facility granted to the assessee is withdrawn as a result of dishonouring of cheques or where the facility is restored subsequently.

1	2	3	4
2. Rule 9	All officers of and above the rank of Asstt. Collectors	The account current shall be maintained in the name of the Collector.	

NOTES—1. In each case such permission should be granted by Asstt. Collector under intimation to the Collector and Chief Accounts Officer.

2. Collector is the appellate authority to whom the assessee could make a representation against refusal of Asstt. Collector to give permission to pay duty through cheques.

3. Column 4 against Sl. No. 2 in Collector's Notification No. 1/71 dt. 4-6-71 stands modified to the above extent.

[Notifn. No. 2/74/CE—Issued from file C. No. IV/8/1/74 MP. 2]
A. S. I. JAFFAR, Collector.

संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, 24 अगस्त, 1974

का० प्र० 3015.—सर्वश्री चोक्सी ब्रदर्स, कांजी मेन्शन, 315 सरदार वी०पी० रोड, बम्बई-4 को सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड एवं सोडियम के डबल साइनाइड आदि के आयात के लिए 1250 रुपये (एक हजार बी सौ पचास रुपए मात्र) का एक लाइसेंस संख्या पी ई/0205356 दिनांक 10-1-72 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति मात्र) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि वह बम्बई सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराने के बाद और उसका बिलकुल उपयोग किए बिना ही खो गया है। अपने दावों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या पी ई/0205356, दिनांक 10-1-72 खो गया है और निदेश देती हूँ कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द किया गया समझा जाना चाहिए।

[का० सं० 1280/22.31.V/578666/AM 72/EI.III से जारी]

कुमारी एस० डी० मराठे, उप-मुख्य नियंत्रक

रुने संयुक्त मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

Bombay, the 24th August, 1974

S.O. 3015.—M/s. Choksi Brothers, Kanji Mansion, 315 Sardar V. P. Road, Bombay-4 has been granted licence No. PE/0205356 dated 10-1-72 for Rs. 1250 (Rupees One thou-

sand two hundred and fifty only) for import of Sodium Cyanide, Potassium Cyanide and double cyanide of Sodium etc.

They have applied for the duplicate copies of the said licence (Custom Purpose copy only) on the ground that the same have been lost after having been registered with Bombay Custom House and unutilised. In support of their claim, applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that the Custom copy of the licence No. PE/0205356 dated 10-1-72 has been lost and direct that the duplicate of the said licence (Custom Purpose copy) should be issued to the applicant firm.

The original Custom purpose copy of the licence should be treated as cancelled.

[Issued from file No. 1280/22. 31. V/578666/AM. 72/EI. III]

KUM. S. D. MARATHE, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1974

का० प्र० 3016.—सर्वश्री इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली को 40,00,000 रुपये के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या : जी/टी/2391598, दिनांक 30-6-72 प्रदान किया गया था। उन्होंने आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क निकासी प्रति) की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि विधवाधीन आयात लाइसेंस उनसे खो गया है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तबनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस खो गया है। इसलिए यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सीसी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली को जारी किए गए मूल आयात लाइसेंस संख्या : जी० टी० 2391598, दिनांक 30-6-72 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या एस पी सी एल/20/आई ओ सी/74-75]

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS & EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 1974

S.O. 3016.—M/s. Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi were granted import licence No. G/T/2391598 dated 30-6-1972 for Rs. 40,00,000. They have applied for the issue of duplicate import licence (Custom Copy) on the ground that import licence in question has been lost by them.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary Maharashtra State, Bombay. I am accordingly satisfied that the original licence has

been lost Therefore, in exercise of the power conferred under sub clause 9(cc) of the Imports (Control) Orders, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original licence No G/T/2391598 dated 30-6-1972 issued to M/s Indian Oil Corporation Ltd, New Delhi is hereby cancelled

3 A duplicate copy of said licence is being issued separately

[No SPCL/20/IOC/74 75]

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3017—सर्वश्री इंडियन आयल कारपोरेशन लि० नई दिल्ली को 25,57,950/-रुपये मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सख्या जी/टी/2500335/दिनांक 11-5-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क निकासी प्रति) की अनुलिपि जारी करने के लिए आयात पर आवेदन किया है कि विषयाधीन आयात लाइसेंस उनसे खो गया है।

2 इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी महाराष्ट्र राज्य बम्बई के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस खो गया है। इसलिए यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री इंडियन आयल कारपोरेशन लि० बम्बई को जारी किए गए उक्त आयात लाइसेंस सख्या जी/टी/2500335 दिनांक 11-5-73 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

3 उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति भ्रम से जागे की जा रही है।

[महेश्वरी आईओसी/1/73-74/आरएम-सेल/स्वे०सेल]

एस० के० उस्मानी, उप-मुख्य नियंत्रक।

ORDER

New Delhi, the 5th October, 1974

S.O. 3017. -M/s Indian Oil Corporation Ltd, New Delhi were granted import licence No G/T/2500335 dated 11-5-73 for Rs. 25,57,950 They have applied for the issue of duplicate import licence (Custom Copy) on the ground that the import licence in question has been lost by them

2 In support of this contention the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary Maharashtra State, Bombay I am accordingly satisfied that the original licence has been lost Therefore, in exercise of the power conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original licence No G/T/2500335 dated 11 5 73 issued to M/s Indian Oil Corporation Ltd, Bombay is hereby cancelled.

3 A duplicate copy of the said licence is being issued separately

[No IOC/1/73-74/RM-Cell/Sp Cell]

S K USMANI, Dy Chief Controller

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3018.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना सं० 8-34/68 सर्वे० 2, दिनांक 4 सितम्बर, 1974 (14-9-1974 को एस० आ० सं० 2362 के रूप में प्रकाशित) में नियम एस० आर० 317-ए एच-3 के उपनियम (1) के अधीन "टाइप V" के नीचे दिए गए "टाइप IV" शब्द के स्थान पर "टाइप VI" पढ़ा जाए।

[फा० सं० 8-34/68 सर्वे०-2]

टी० एल० विष्णुनाथन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th October, 1974

S.O. 3018.—In the Department of Science and Technology Notification No 8 34/68-Sur 2, dated the 4th September, 1974 (Published as S O No 2362 on 14-9-1974) the word "Type IV" appearing below "Type V" under Sub-rule (i) of Rule S R 317-AH-3 shall be substituted to read as "Type VI".

[F No 8-34/68-Sur 2]

T L VISWANATHAN, Under Secy

उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3019.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषद् (कार्यविधिका) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस० एम० चक्रवर्ती, निदेशक (वस्त्र), भारतीय मानक सस्था, नई दिल्ली को 19-4-1976 तक के लिए वस्त्र मशीनों के निर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश का० आ० 1134 दिनांक 20-4-74 द्वारा स्थापित वस्त्र मशीन उद्योग की विकास परिषद् का सदस्य नामित करती है और निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

29 श्री एस० एम० चक्रवर्ती, निदेशक (वस्त्र), भारतीय मानक सस्था, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110001।

[सं० 2-2/71-एच एम (1)]

एस० कन्नन, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 26th October, 1974

ORDER

S.O. 3019.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules 1952, the Central Government hereby nominates till 19-4-1976, Shri S M Chakraborty, Director (Textile) Indian Standards Institute, New Delhi to be a member of the Development Council for Textile Machinery Industry established by the order of the Government

of India in the Ministry of Heavy Industry S.O. 1134 dated 20-4-74 for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Textile Machinery and directs that the following addition shall be made in the said order, namely —

29 Shri S. M. Chakraborty,
Director (Textiles)
Indian Standards Institute.
Manak Bhavan,
9, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi 110001

[No 2-2/71-HM(I)]

S KANNAN, Under Secy

प्रौद्योगिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 1974

क्र० प्रा० 3020 — भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि गोद लगे कागज के टेप की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दी गई ब्यौरा के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस 1 अगस्त, 1973 से लागू हो जाएगी।

अनुसूची

क्रम सं०	उत्पाद / उत्पाद की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की पदमख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1	गोद लगे कागज के टेप	IS 4185--1967 गोद लगे कागज के टेप की विशिष्टि	20 रोल की एक गांठ	35 पैसे

[सं० सी०एम०डी०/13 10]

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 29th October, 1974

S O 3020 —In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee per unit for gummed paper tapes, details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1 August, 1973.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gummed paper tapes	IS. 4185-1967 Specification for gummed paper tapes	One bale of 20 rolls	35 Paise

[No CMD/13 . 10]

क्र० प्रा० 3021.—समय समय पर सशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०एम०/एल-1616, 1617 और 2089 जिसके ब्यौरा नीचे दिए गए हैं, फर्म द्वारा केबलों का उत्पादन बंद कर देने के कारण 1 जुलाई 1974 से रद्द कर दिए गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
1 सी०एम०/एल-1616 11 जनवरी, 1968	भमसं अजवासी इन्सुलेटेड केबल कम्पनी, 4/19, भुवनेश्वर रोड, मयुरा (उ०प्र०)	रबड़ रोधित केबल-मार्का 'सुपर अजवासी'	(1) IS 434(भाग 1)-1964 रबड़ रोधित केबलों की विशिष्टि भाग 1 तांबे के चालको वाले (पुनरीक्षित) (2) IS 434(भाग 2)-1964 रबड़ रोधित केबलों की विशिष्टि भाग 2 एल्युमिनियम चालको वाले (पुनरीक्षित)

[सं० सी०एम०डी०/55 1616 (इटी)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सी०एम०/एल०-1617 11 जनवरी, 1968	मेसर्स ब्रजवासी इंसुलेटेड केबल कम्पनी, पी० बी० सी० रोडित केबल- 4/19, भूतेश्वर रोड, मथुरा (उ०प्र०)	मार्का: 'सुपर ब्रजवासी'	(1) IS 694(भाग 1)—1964 पी०बी०सी० रोडित केबलों की विशिष्ट (1100 वो० तक कार्यकारी वोल्टता के लिए): भाग 1 तांबे के चालकों वाले (पुनरीक्षित)	(2) IS:694(भाग 2)—1964 पी०बी०सी० रोडित केबलों की विशिष्ट (1100 वो० तक कार्यकारी वोल्टता के लिए): भाग 2 एल्युमिनियम चालकों वाले (पुनरीक्षित)
3. सी०एम०/एल-2089 30-9-1969	"	ताप नम्य रोडित क्रसुतह केबल-मार्का: 'सुपर ब्रजवासी,'	(1) IS:3035(भाग 2)—1965 तापनम्य रोडित क्रसुतह केबलों की विशिष्ट भाग 1 पी०बी०सी० रोडित और पी०बी०सी० खोल वाले;	(2) IS:3035(भाग 2)-1965 ताप नम्य रोडित क्रसुतह केबलों की विशिष्ट भाग 2 पोलीइथाइलीन रोडित टेप लगे अथवा रहित, बंडेड और सहमित- (3) IS:3035(भाग 3)—1967 तापनम्य रोडित क्रसुतह केबलों की विशिष्ट भाग 3 पोलीइथाइलीन रोडित और पोलीइथाइलीन खोलवाले-

[स०सी०एम०बी० / 55:1616(एटी)]

S. O. 3021.— In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM/L-1616, 1617 and 2089 particulars of which are given below have been cancelled with effect from 1 July, 1974 as the firm has stopped the production of cables:-

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licences cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-1616 11 Jan, 1968	M/s Brijbasi Insulated Cable Company. 4/19 Bhuteshwar Road, MATHURA (U.P.)	Rubber-insulated cables- Brand: SUPER BRIJBASI	(1) IS:434 (Part I)—1964 Specification for rubber insulated cables Part I with copper conductors (Revised) (2) IS: 434 (Pt. II)—1964 Specification for rubber insulated cables Part II with aluminium conductors (Revised)
2.	CM/L-1617 11 Jan., 1968	-do-	PVC insulated cables Brand- SUPER-BRIJBASI	(1) IS:694 (Part I—1964) Specification for PVC insulated cables (for voltages up to 1100 volts) Part I with copper conductors (Revised) (2) IS: 694 (Part II—1964) Specification for PVC insulated cables (for voltages up to 1100 volts (Part II with aluminium conductors (Revised)
3.	CM/L-2089 30-9-1969	-do-	Thermoplastic insulated weatherproof cables Brand: 'SUPER-BRIJBASI'	(1) IS:3035 (Part I) - 1965 Specification for thermoplastic insulated weather-proof cables, Part I PVC insulated and PVC sheathed (2) IS: 3035 (Part II)—1965 Specification for thermoplastic insulated weather-proof cables, Part II polyethylene insulated, taped or untaped, braided and compounded (3) IS: 3035 (Part III)—1967 Specification for thermoplastic insulated weather-proof cables Part III polyethylene insulated and polyethylene sheathed

क्रा०प्रा० 3022.....समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०एम०/एन० 3617 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, फेक्ट्री के श्रमिक झगड़ों के कारण बंद हो जाने पर 1 दिसम्बर, 1973 से रद्द कर दिया गया है :

अनुसूची

क्रम संख्या लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंस धारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया तत्संबंधी भारतीय मानक
सी०एम०/एन० 3617 30-11-73	मैसर्स लायड बिट्यूमेन प्रोडक्ट्स० प्रा० लि० जलसह कार्यों के लिए बिट्यूमेन (प्लास्टिक) आई एस: 1580-1969 1, तारतल्ला रोड, कलकत्ता-53 इनका मार्का-प्लास्टोलॉयड कार्यालय : 4ए, रोड स्ट्रीट कलकत्ता-16 में है।	

[म०(सी०एम०डी०) 55:3617]

ए० के० गुप्ता, उप महानिदेशक

New Delhi, the 29 October, 1974

S.O. 3022. —.....In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-3617 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1 Dec. 1973 on account of/due to Closure of the factory due to labour trouble.

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Governed by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	CM/L-3617 30-11-73	M/s Lloyd Bitumen Products Pvt. Ltd., 1, Taratalla Road, Calcutta-53 having their office at 4-A, Royd Street, Calcutta-16.	Bitumen (Plastic) for Water-proofing Purposes Brand : 'PLASTOLOID'	IS : 1580-1969

[No. CMD/55 : 3617]

A.K. Gupta Deputy Director general

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर, 1974

क्रा०प्रा० 3023.— समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के अधीन प्राप्त अधिकारियों के अनुसार कुछ भारतीय मानकों के उपबंधों में जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, मानक चिन्ह के उपयोग में गति लाने के उद्देश्य से परीक्षार्थक रूप में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के द्वारा भारतीय मानकों के अनुरूप बने माल की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये संशोधन तुरन्त ही लागू हो जाएंगे ;

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक जिसने उपबंधों में संशोधन किए गए हैं	भारतीय मानकों के उपबंधों में किए गए संशोधनों का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	आई० एस० 1812-1973 लकड़ी पेंच बनाने के लिए मृदु इस्पात	इस विशिष्ट में सिल्लियां तथा पिंड शामिल कर लेने की व्यवस्था की गई है। के तार (पहला पुनरीक्षण)
2.	आई० एस० 2255-1969 मशीनी पेंच बनाने के लिए मृदु इस्पात के तार (सिरे बनाने की शीत विधि द्वारा) (पहला पुनरीक्षण)	तबेव
3.	आई० एस० 2589-1964 गद्दी वाली कमानियों के लिए सख्त खिचे इस्पात के तार	तबेव
4.	आई० एस० 2879-1967 मेटल आर्क वैल्विंग इलेक्ट्रोड कोर के तार के लिए मृदु इस्पात (पहला पुनरीक्षण)	तबेव
5.	आई० एस० 3195-1965 शंखावर्त तथा कुण्डलीदार कमानियों के लिए इस्पात (रेल के डिब्बों के लिए)	तबेव

1	2	3
6. आई० एस० 3431-1965 स्क्वेल गार्डियों में निलम्बन के लिए शंखावर्त तथा कुण्डलीदार और परतदार कमानियों के बनाने के लिए हस्तात		इस विधिष्टि में सिलिसिया तथा पिंड शामिल कर लेने की व्यवस्था की है ।
7. आई० एस० 3885 (भाग 1)-1966 परतदार कमानियाँ बनाने के लिए हस्तात (रेल के डिब्बों के लिए) भाग 1-चपटे सेक्शन		"
8. आई० एस० 3885 (भाग 2)-1966 परतदार कमानियाँ बनाने के लिए हस्तात (रेल डिब्बों के लिए) भाग-2 फॉक (रिब) और खांच सेक्शन		"
9. आई० एस० 4072-1967 स्प्रिंग वाशरों के लिए हस्तात		"

[सं० सी०एम०डी०/13:4]

एस० के० सेन, महानिदेशक

New Delhi, 1 November, 1974

S.O. 3023.—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of various Indian standards, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without anyway affecting the quality of goods covered by the relevant standard. These modifications shall come into force with immediate effect :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard Specification, the provision of which have been modified	Particulars of the modifications made to the Provisions
(1)	(2)	(3)
1.	IS : 1812-1973 Mild steel wire rods for the manufacture of wood screws (first revision).	Provision has been made to include ingots and billets in this specification.
2.	IS : 2255-1969 Mild steel wire rod for the manufacture of machine screws (by cold heading process) (first revision).	Do.
3.	IS : 2589-1964 Hard-drawn steel wire for upholstery springs	Do.
4.	IS : 2879-1967 Mild steel for metal arc welding electrode core wire (first revision).	Do.
5.	IS : 3195-1965 Steel for the manufacture of volute and helical spring (for railway rolling stock).	Do.
6.	IS : 3431-1965 Steel for the manufacture of volute, helical and laminated springs for automotive suspension.	Do.
7.	IS : 3885 (Part I)—1966 Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part I—Flat Sections.	Do.
8.	IS : 3885 (Part II)—1969 Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part II—Rib and groove sections.	Do.
9.	IS : 4072-1967 Steel for spring washers	Do.

[No. CMD/13 : 4]

S. K. SEN, Director General.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1974

का० अा० 3024.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया राज्य पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय नैल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः ऐसी साहनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय तेल निगम लि० सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट "डोली"-33-बी, हरिहर सोसा-इटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : चोटीला

जिला : सुरेन्द्रनगर

गुजरात : राज्य

ग्राम	सर्वेक्षण सं०	एच	क्षेत्र ए	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
जानीबादला	60	0	06	07
	61	0	27	32
	62	0	14	16
	71	0	03	04
	70	0	15	18
	69	0	16	19
	67	0	18	21
	182	0	24	28
	181	0	24	05
	184	0	06	07
	185	0	08	09
	186	0	15	18
	194	0	09	12
	193	0	20	23
	187	0	06	07
	215	0	38	45
	232	0	22	26
	231	0	20	23
	229	0	31	36
	258	0	23	27
	259	0	02	02
	256	0	19	22
	255	0	04	05
	260	0	01	01
	261	0	17	20
	263	0	07	08
	264	0	08	09
	265	0	20	23
बन्पा	17	0	41	48
	18	0	11	13
	15	0	11	13
चोटिला	196	0	42	49
	198	0	03	04
	199	0	31	36

1	2	3	4	5
चोटिला	171	0	25	29
	173	0	18	19
	179	0	01	01
	174	0	42	49
	175 पी/1	0	08	07
	175 पी/2	0	06	07
नवगांव (चो०)	65 पी	0	55	64
	66 पी	0	43	50
	67 पी	0	04	05
पोशवाली	97	0	12	14
	98	0	30	35
	1	0	03	04
	105	0	14	16
	106/1	0	10	12
	107	0	07	08
	108	0	06	07
	110	0	18	21
	101 पी/1	0	02	02
	101 पी/2	0	08	09
	101 पी/4	0	04	05
	101 पी/4	0	21	25
	101 पी/5	0	25	29
रूपवती (चो०)	47	0	04	05
	54	0	28	33
	57	0	32	57
	68	0	07	08
	87	0	87	01
	94 पी/1	0	41	48
	94 पी/2	0	21	25
	95 पी	0	01	01
	3	0	02	02
नाभा	10	0	30	35
	11	0	01	01
	137 पी/1	0	12	14
	137 पी/2	0	39	46
	135	0	24	28
	134	0	22	26
	137 पी/3	0	16	28
	137 पी/4	0	31	36
	137 पी/5	0	14	16
	127	0	14	16
	137 पी/6	0	13	15
	128	0	13	15
	130	0	43	50
	137 पी/7	0	01	02
	137 पी/8	0	28	33
	137 पी/9	0	26	30

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
देवसर	83 पी/1	0	17	20		184	0	06	07
	66/1	0	17	20		185	0	08	09
	66/2	0	21	25		186	0	15	18
	83 पी/2	0	18	22		194	0	09	10
	70	0	19	22		193	0	20	23
	83 पी/3	0	10	12		187	0	06	07
	71	0	49	57		215	0	38	45
	75	0	45	53		232	0	22	26
	76	0	22	26		231	0	20	23
	77 पी/1	0	37	43		229	0	31	36
	83 पी/4	0	02	02		258	0	23	27
	77 पी/2	2	27	64		259	0	02	02
	77 पी/3	0	49	57		256	0	19	22
	78	0	58	68		255	0	04	05
						260	0	01	01
						261	0	17	20
						263	0	07	08
						264	0	08	09
						265	0	20	23

(संख्या 12017/3/74-एल० तथा एल०/IV]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, 31st October, 1974

S. O. 3024.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Hachar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka :—Chotila. District :—Surendranagar, Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H	A.	Sq. M.
Janivadla	60	0	06	07
	61	0	27	32
	62	0	14	16
	71	0	03	04
	70	0	15	18
	69	0	16	19
	67	0	18	21
	182	0	24	28
	181	0	04	05

Chanpa	17	0	41	48
	16	0	11	13
	15	0	11	13
Chotila	196	0	42	49
	198	0	03	04
	199	0	31	36
	171	0	25	29
	173	0	16	19
	179	0	01	01
	174	0	42	49
	175 P/1	0	06	07
	175 P/2	0	06	07
Navagam (Cho.)	65 P.	0	55	64
	66 P.	0	43	50
	67 P.	0	04	05
Pojvali	97	0	12	14
	98	0	30	35
	1	0	03	04
	105	0	14	16
	106/1	0	10	12
	107	0	07	08
	108	0	06	07
	110	0	18	21
	101 P/1	0	02	02
	101 P/2	0	08	09
	101 P/3	0	04	05
	101 P/4	0	21	25
	101 P/5	0	25	29
Rupavati (Cho.)	47	0	04	05
	54	0	28	33
	57	0	32	37
	68	0	07	08
	87	0	87	01
	94 P/1	0	41	48
	94 P/2	0	21	25
	95 P.	0	01	01
	3	0	02	02

1	2	3	4	5
Nava	10	0	30	35
	11	0	01	01
	137 P/1	0	12	14
	137 P/2	0	39	46
	135	0	24	28
	134	0	22	26
	137 P/3	0	16	28
	137 P/4	0	31	36
	137 P/5	0	14	16
	127	0	14	16
	137 P/6	0	13	15
	128	0	13	15
	130	0	43	50
	137 P/7	0	01	02
	137 P/8	0	28	33
	137 P/9	0	26	30
Devsar	83 P/1	0	17	20
	66/1	0	17	20
	66/2	0	21	25
	83 P/2	0	18	22
	70	0	19	22
	83 P/3	0	10	12
	71	0	49	57
	75	0	45	53
	76	0	22	26
	77 P/1	0	37	43
	83 P/4	0	02	02
	77 P/2	2	27	64
	77 P/3	0	49	57
	78	0	58	68

[No. 12017/3/74-L & L/IV]

क्र०अ०३०२५.—यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मलाया प्लतन में उत्तर प्रदेश में मथुरा तथा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यन ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवुपाबड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग न करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनद्वारा जोरित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लि०, मलाया-कोयासी/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "होली"-33-बी, हरिद्वार सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची				
तापुका वधाना	जिला: सुरेन्द्रनगर	गुजरात: राज्य		
ग्राम	सर्वेक्षण सं०	क्षेत्र		
		एक	ए	वर्ग मीटर
वमारगंज	167	0	28	23
	165	0	42	49
	164	0	30	35
	163	0	16	19
	162	0	15	18
	160	0	29	34
	161	0	04	05
	153/1	0	03	04
	152	0	31	36
	150/2	0	15	18
	150/3	0	05	06
	89/2	0	15	18
	89/1	0	09	11
	37/2	0	06	07
	39/1	0	21	25
	35/2	0	02	02
	35/1	0	14	17
	39/4	0	03	04
	33	0	29	34
	6/1	0	20	23
	357	0	18	21
	356	0	21	25
	355	0	00	10
	354	0	26	30
	353	0	13	15
	352	0	11	13
	351	0	10	12
	343	0	02	02
	300	0	14	16
	307/पी/1	0	37	43
	307/पी/2	0	27	29
	310	0	35	41
	311	0	02	02
	315/पी/1	0	18	28
	315/पी/2	0	23	27
	314	0	05	06
	316	0	13	15
	317	0	40	47
दुधरेज	28	0	49	57
	32	0	00	36
	223	0	04	05
	210	0	00	06
	211	0	45	53
	212	0	35	41
	224	0	36	42

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	225	0	30	35		331	0	36	42
	226	0	10	12		329	0	39	46
	229/1/पी	0	05	06		321	0	40	47
	272	0	08	09		243	0	15	18
	276 पी	0	02	02		244	0	04	05
	273	0	34	40		320	0	05	06
	270	0	24	28		319	0	09	11
	265	0	22	26		318	0	12	14
	268	0	20	23		317	0	22	26
	269	0	11	13		252	0	29	34
	23	0	09	11		253/1	0	12	14
	972	0	22	25		254	0	12	14
	973	0	11	13		255	0	26	30
	885	0	14	16		256/1	0	19	22
	890	0	15	18		256/2	0	01	01
	889	0	15	18		257	0	05	06
	887	0	42	49		260	0	00	10
	888	0	11	13		259	0	31	36
	892	0	00	10		258	0	32	37
	874	0	18	21		270	0	18	21
	875	0	27	32	बामा	262	0	05	06
	876	0	55	64		261	0	35	41
	860/2	0	23	27		260	0	01	01
बकरवाली	266	0	63	64		259	0	31	36
	269	0	04	05		257	0	14	16
	268	0	19	22		258	0	84	98
	267	0	03	04		251	0	33	39
	256	0	25	29		249	0	23	27
	280	0	44	52		248	0	25	29
	279	0	13	15		247	0	09	11
	288	0	32	37		246	0	01	01
	290	0	38	45		245	0	26	30
	291	0	41	48		440	0	06	07
	11	0	31	36		239	0	20	23
	18	0	24	28		215	0	35	41
	17	0	20	23		218	0	14	16
	19	0	29	34		219	0	30	35
	20	0	06	07		220	0	11	13
	23	0	01	01		173	0	59	69
	22	0	32	37		172	0	01	01
	21	0	03	04		169	0	13	15
	32	0	18	21	प्रविन्दा	674	0	27	32
	36	0	37	43		675	0	24	28
राजपार	24	0	05	06		680	0	33	39
	22	0	32	37		679	0	21	25
	395	0	26	30		688	0	23	27
	394	0	16	19		687	0	27	32
	378	0	03	04		702	0	39	46
	379	0	24	28		701	0	23	27
	332	0	25	29		704	0	01	01

1	2	3	4	5
मनिम्रा-जारी	703	0	38	45
	33	0	27	32
	34	0	09	11
	50	0	33	39
	51	0	24	28
	57	0	22	26
	58	0	27	32
	66	0	01	01
	67	0	15	18
	68	0	23	27

[संख्या 12017/3/74-एल० तथा एल० V]

S.O. 3025—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Wadhwan District :—Surendranagar Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2	3	4	5
Chamaraaj	167	0	28	23
	165	0	42	49
	164	0	30	35
	163	0	16	19
	162	0	15	18
	160	0	29	34
	161	0	04	05
	153/1	0	03	04
	152	0	31	36
	150/2	0	15	18
	150/3	0	05	06
	89/2	0	15	18
	89/1	0	09	11

1	2	3	4	5
	37/2	0	06	07
	39/1	0	21	25
	35/2	0	02	02
	35/1	0	14	17
	39/4	0	03	04
	33	0	29	34
	6/1	0	20	23
	357	0	18	21
	356	0	21	25
	355	0	00	10
	354	0	26	30
	353	0	13	15
	352	0	11	13
	351	0	10	12
	343	0	02	02
	300	0	14	16
	307 P/1	0	37	43
	307 P/2	0	27	29
	310	0	35	41
	311	0	02	02
	315 P/1	0	18	28
	315 P/2	0	23	27
	314	0	05	06
	316	0	13	15
	317	0	40	47
Dudhrej	28	0	49	57
	32	0	00	36
	223	0	04	05
	210	0	00	06
	211	0	45	53
	212	0	35	41
	224	0	36	42
	225	0	30	35
	226	0	10	12
	229/1 P	0	05	06
	272	0	08	09
	276 P.	0	02	02
	273	0	34	40
	270	0	24	28
	265	0	22	36
	268	0	20	23
	269	0	11	13
	23	0	09	11
	972	0	22	25
	973	0	11	13
	885	0	14	16
	890	0	15	18
	889	0	15	18
	887	0	42	49
	888	0	11	13
	892	0	00	10
	874	0	18	21
	875	0	27	32
	876	0	55	64
	860/2	0	23	27
Bakarthali	266	0	63	64
	269	0	04	05
	268	0	19	22
	267	0	03	04
	256	0	25	29
	280	0	44	52
	279	0	13	15
	288	0	32	37
	290	0	38	45
	291	0	41	48
	11	0	31	36
	18	0	24	28
	17	0	20	23
	19	0	29	34
	20	0	06	07
	23	0	01	01
	22	0	32	37
	21	0	03	04
	32	0	18	21
	36	0	37	43
Rajpar	24	0	05	06
	22	0	32	37
	395	0	26	30
	394	0	16	19
	378	0	03	04

1	2	3	4	5
	379	0	24	28
	332	0	25	29
	331	0	36	42
	329	0	39	46
	321	0	40	47
	243	0	15	18
	244	0	04	05
	320	0	05	06
	319	0	09	11
	318	0	12	14
	317	0	22	26
	252	0	29	34
	253/1	0	12	14
	254	0	12	14
	255	0	26	30
	256/1	0	19	22
	256/2	0	01	01
	257	0	05	06
	260	0	00	10
	259	0	31	36
	258	0	32	37
	270	0	18	21
Bala	262	0	05	06
	261	0	35	41
	260	0	01	01
	259	0	31	36
	257	0	14	16
	258	0	84	98
	251	0	33	39
	249	0	23	27
	248	0	25	29
	247	0	09	11
	246	0	01	01
	245	0	26	30
	440	0	06	07
	239	0	20	23
	215	0	35	41
	218	0	14	16
	219	0	30	35
	220	0	11	13
	173	0	59	69
	172	0	01	01
	169	0	13	15
Anindra	674	0	27	32
	675	0	24	28
	680	0	33	39
	679	0	21	25
	688	0	23	27
	687	0	27	32
	702	0	39	46
	701	0	23	27
	704	0	01	01
	703	0	38	45
	33	0	27	32
	34	0	09	11
	50	0	33	39
	51	0	24	28
	57	0	22	26
	56	0	27	32
	66	0	01	01
	67	0	15	18
	68	0	23	27

[No 12017/3/74-L&L/V]

क्रा० क्र० 3028.—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तम से उत्तर प्रदेश में मथुरा तथा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय नैल निगम लि० द्वारा बिछाई जायी जाहिए ।

और यत् ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अतुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय नैल निगम लि० सलाया-कोयली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोपी"-33-बी, हरिहर सासाहटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अतुसूची

तालुका	दमदा	जिसा-सुरेन्द्रनगर	गुजरात	राज्य
क्षेत्र				
ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	एक	ए	वर्ग मीटर
हेबनपुर	440	0	12	14
	439	0	11	13
	435	0	01	01
	436	0	36	42
	429	0	12	14
	428	0	01	01
	427/1	0	11	13
	427/2	0	14	16
	427/3	0	01	01
	380	0	03	03
	381	0	50	59
	382	0	11	13
	329	0	32	37
	330	0	18	21
	326	0	37	43
	288	0	11	13
	287	0	15	18
	252	0	48	56
	247/1	0	12	14
	248	0	00	55
	244	0	00	25
	243	0	36	42
	230	0	08	09
	229	0	18	21
	152	0	25	29
	99	0	21	25
	151	0	10	12

1	2	3	4	5
	100 पी०	0	14	16
	102	0	40	47
	103	0.00	00	25
	81	1	70	98

[संख्या 12017/3/74-एल तथा एल/VI]

S.O. No. 3026.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And Whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its Intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Dasada District : Surendranagar Gujarat State.

Village	Survey No.	Extent	Q. M.	
1	2	3	4	5
Hebatpur	440	0	12	14
	439	0	11	13
	435	0	01	01
	436	0	36	42
	429	0	12	14
	428	0	01	01
	427/1	0	11	13
	427/2	0	14	16
	427/3	0	01	01
	380	0	03	03
	381	0	50	59
	382	0	11	13
	329	0	32	37
	330	0	18	21
	326	0	37	43
	288	0	11	13

1	2	3	4	5
	287	0	15	18
	252	0	48	56
	247/1	0	12	14
	248	0	00	55
	244	0	00	25
	243	0	36	42
	230	0	08	09
	229	0	18	21
	152	0	25	29
	99	0	21	25
	151	0	10	12
	100P.	0	14	16
	102	0	40	47
	103	00.0	00	25
	81	1	70	98

[No. 12017/3/74-L&L/VI]

का०आ०सं० 3027—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया परतन उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यत. ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :]

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (9162 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है ।]

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी भारतीय तेल निगम लि० सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33-बी, हरिहर सोसाइटी राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।]

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विशिष्ट व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तालुका : मोरवी	जिला : राजकोट;	गुजरात राज्य		
ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	एक	क्षेत्र	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
ग्रामद्वपार	45	0	28	33
	47	0	46	54
	49	0	20	23
	76	0	24	28

SCHEDULE

75	0	44	52
71	0	01	01
71	0	33	39
81	0	28	33
82	0	24	28
83	0	49	57
93	0	17	20
2 पी/1	0	19	22
2 पी/2	0	11	13
2पी/3	0	22	24
2पी/2	0	15	18
2पी/5	0	20	23
130	0	19	22
131	0	40	47
2पी/6	0	18	21
2पी/7	0	18	21
129	0	26	30
2पी/8	0	18	21
2पी/9	0	06	07
2पी/10	0	19	22
161	0	12	14
162	0	08	09
156	0	24	16
158	0	06	08
157	0	15	18
153	0	02	02
152	0	52	61

[संख्या 12017/3/74-एल तथा एल/VII]

S.O. 3027.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And Whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962); the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

Provided That any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "Doli" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

Taluka : Morvi	District : Rajkot	Gujarat State			
Village	Survey No.	H	Extent A.	Sq. M.	
Anandpar	45	0	28	33	
	47	0	46	54	
	49	0	20	23	
	76	0	24	28	
	75	0	44	52	
	73	0	01	01	
	74	0	33	39	
	81	0	28	33	
	82	0	24	28	
	83	0	49	57	
	93	0	17	20	
	2 P/1	0	19	22	
	2 P/2	0	11	13	
	2 P/3	0	22	24	
	2 P/4	0	15	18	
	2 P/5	0	20	23	
	130	0	19	22	
	131	0	40	47	
	2 P/6	0	18	21	
	2 P/7	0	18	21	
	129	0	26	30	
	2 P/8	0	18	21	
	2 P/9	0	06	07	
	2 P/10	0	19	22	
	161	0	12	14	
	162	0	08	09	
	156	0	24	16	
	158	0	06	08	
	157	0	15	18	
	153	0	02	02	
	152	0	52	61	

[No. 12017/3/74-L&L/VII]

क्रा०स्रा० 3028.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्टन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एनदुपायबद्ध भूमि में अतिरिक्त भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उक्त भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए, आक्षेप सहित अधिकारी, भारतीय तेल निगम लि०, मलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "कोली"-33-बी, हरिद्वार सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका . डरोल	जिला . जामनगर	गुजरात . राज्य		
ग्राम	सर्वेक्षण सं०	एक क्षेत्र वर्ग	ए	मीटर
1	2	3	4	5
जालिया देवानी	109	0	17	00
	108/3	0	16	00
	108/2	0	10	00
	176 पी	0	02	00
	131	0	18	00
	126	0	15	00
	132	0	38	00
	133	0	33	00
	135	0	01	11
	162/1	0	94	14
	162/2	0	07	08
	161/1	0	01	01
	160/3	0	01	01
सिज्जाविया	8	0	66	00
	9	0	47	00
	10	0	35	41
	14	0	00	01
	31/2	0	00	01
	33/1	0	36	49
	32/1	0	38	45
	32/2	0	36	45
	35/1	0	57	67
	35/2	0	42	49
	36	0	60	70
	38	0	01	01
	40	0	24	28
	43	0	23	27
	37	0	39	46
	91/1	0	11	00
	91/2	0	09	11
	91/3	0	17	20
पीपारलोवा	11	0	39	49
	14	0	36	43
	15	0	37	43
	18	0	56	66

1	2	3	4	5
	19	0	20	23
	21	0	20	25
	26	0	26	30
	39	0	03	04
खेतगरका	148	0	20	25
	149	0	15	18
	150	0	15	18
	151	0	21	25
	152	0	23	27
	170/1	0	22	26
	171	0	39	46
	175	0	03	04
	169	0	17	22
कटाबा	2	0	17	20
	3	0	10	08
	4	0	41	48
	5	0	00	08
	6	0	23	27
	7	0	26	30
	35	0	23	27
	65	0	21	25
	67	0	07	08
	69	0	07	08
	70	0	03	04
	71	0	10	00
	72	0	06	07
	74	0	28	33
	75	0	23	27
	111	0	37	43
	120	0	04	05
	122	0	11	13
	123	0	11	13
	126	0	23	27
	127	0	38	45
	128	0	19	22
	14	0	09	11
	121	0	13	00

[संख्या 12017/3/74-एल तथा एल/VIII]

S.O. 3028.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Dhrol District : Jamnagar Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		Sq.
		H.	A.	M.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Jalia Devani	109	0	17	00
	108/1	0	16	00
	108/2	0	10	00
	176 P	0	02	00
	131	0	18	00
	126	0	15	00
	132	0	38	00
	133	0	33	00
	135	0	01	11
	162/1	0	94	14
	162/2	0	07	08
	161/1	0	01	01
	160/3	0	01	01

Khijadia	8	0	66	00
	9	0	47	00
	10	0	35	41
	14	0	00	01
	31/2	0	00	01
	33/1	0	36	49
	32/1	0	38	45
	32/2	0	36	45
	35/1	0	57	67
	35/2	0	42	49
	36	0	60	70
	38	0	01	01
	40	0	24	28
	43	0	23	27
	37	0	39	46
	91/1	0	11	00
	91/2	0	09	11
	91/3	0	17	20

Pipartoda	11	0	39	49
	14	0	36	43
	15	0	37	43
	18	0	56	66
	19	0	20	23
	21	0	21	25
	26	0	26	30
39	0	03	04	

1	2	3	4	5
Khengarka	148	0	20	25
	149	0	15	18
	150	0	15	18
	151	0	21	25
	152	0	23	27
	170/1	0	22	26
	171	0	39	46
	175	0	03	04
Katada	169	0	17	22
	2	0	17	20
	3	0	10	08
	4	0	41	48
	5	0	00	08
	6	0	23	27
	7	0	26	30
	35	0	23	27
	63	0	21	25
	67	0	07	08
	69	0	07	08
	70	0	03	04
	71	0	10	00
	72	0	06	07
	74	0	28	33
	75	0	23	27
	111	0	37	43
	120	0	04	05
	122	0	11	13
	123	0	11	13
	126	0	23	27
	127	0	38	45
	128	0	19	22
	14	0	09	11
	121	0	13	00

[No. 12017/3/74-L&L/VIII]

का० प्रा० 3029.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः ऐसी साहनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लि० सलाया-कोयाली/ मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट "डोली"-33-बी त्रिहर सोसाइटी राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तालुका : लालपुर	जिला :—जामनगर	गुजरात	राज्य	
ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र एच ए	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5
सिंगाच	313	0	14	00
	316	0	42	00
	318	0	47	00
	320/3	0	13	00
	320/2	0	18	00
	320/1	0	00	02
	282	0	01	50
	283	0	32	00
	259	0	11	00
	258	0	08	00
	257	0	14	00
	256	0	19	00
	263	0	09	00
	236	0	33	00
	233	0	00	25
	147	0	25	00
	143	0	19	00
	137 पी	0	40	41
	139 पी	0	46	00
	133	0	23	00
	138/2	0	27	00
	138/3	0	02	00
शंकार	490	0	18	00
	489	0	21	00
	488	0	23	00
	81	0	22	00
	494	0	16	00
	65	0	06	00
	487	0	33	00
	486	0	18	00
	502	0	08	00
	503	0	01	00
	504	1	09	00
	519	0	08	00
	520	0	25	00

1	2	3	4	5
शंकार	528	0	24	00
	526	0	01	00
	525	0	08	00
	176	0	09	00
	177	0	18	00
	179	0	02	00
	180	0	09	00
	158	1	00	00
	155	0	26	00
	156	0	37	00
	138	1	02	00
जोगदव	82	0	28	00
	81	0	32	00
	80	0	27	00
	76	0	22	00
	75	0	14	00
	211	0	01	00
	194	0	07	00
	212	0	25	00
	213	0	14	00
	215	0	14	00
	168	0	58	62
	167	0	04	00
	166	0	31	00
	147	0	32	00
	145	0	22	00
	144	0	04	00
	148	0	22	00
	143	0	63	00
	152	0	13	00
	141	0	33	00
	139	0	18	00
	138	0	17	00
	136	0	33	00
	135	0	42	00
	133	0	28	00
	132	0	01	00

[संख्या 12017/3/74-एल० तथा एल०/IX]

New Delhi, the 31st October 1974

S.O. No. 3029.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka: Talpur District: Jamnagar Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2	5		
SINGACH	313	0	14	00
	316	0	42	00
	318	0	47	00
	320/3	0	13	00
	329/2	0	18	00
	320/1	0	00	02
	282	0	01	50
	283	0	32	00
	259	0	11	00
	258	0	08	00
	257	0	14	00
	256	0	19	00
	263	0	09	00
	236	0	33	00
	233	0	00	25
	147	0	25	00
	143	0	19	00
	137 P	0	40	41
	139 P	0	46	00
	135	0	23	00
	138/2	0	27	00
	138/3	0	02	00
ZANKHAR	490	0	18	00
	489	0	21	00
	488	0	23	00
	81	0	22	00
	494	0	16	00
	65	0	06	00
	487	0	33	00
	486	0	18	00
	502	0	08	00
	503	0	01	00
	504	1	09	00
	519	0	08	00
	520	0	25	00
	528	0	24	00
	526	0	01	00
	525	0	08	00
	176	0	09	00
	177	0	18	00
	179	0	02	00
	180	0	09	00
	158	1	00	00
	155	0	26	00
	156	0	37	00
	138	1	02	00

1	2	3
JOGVAD	82	0 28 00
	81	0 32 00
	80	0 27 00
	76	0 22 00
	75	0 14 00
	211	0 01 00
	194	0 07 00
	212	0 25 00
	213	0 14 00
	215	0 14 00
	168	0 58 62
	167	0 04 00
	166	0 31 00
	147	0 32 00
	145	0 22 00
	144	0 04 00
	148	0 22 00
	143	0 63 00
	152	0 13 00
	141	0 33 00
	139	0 18 00
	138	0 17 00
	136	0 33 00
	135	0 42 00
	133	0 28 00
	132	0 01 00

[No. 12017/3/74 L&L/IX]

का० धा० 3030.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उक्त भूमि के भीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लि०, सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डौली"-33 बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को हम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी मार्फत।

प्रमुख सूची				(1)	(2)	(3)	
तालुका : जामनगर	जिला : जामनगर	गुजरात : राज्य			293	0	11 00
ग्राम	सर्वेक्षण सं०	एच	क्षेत्र ए वर्ग मीटर		278	0	16 00
(1)	(2)	(3)			265	0	27 00
मोरकाडा	231	0	15 00		276	0	04 00
	216	0	16 00		277	0	16 00
	213	0	35 00		275	0	28 00
	212	0	05 00		267	0	06 00
	142	0	26 00		208	0	27 00
	143/2	0	07 00		206	0	14 00
	144	0	09 00		164/1	0	23 00
	145/1	0	22 00		164/2	0	13 00
	145/2	0	18 00		164/3	0	15 00
	156	0	55 00		165/1	0	28 00
	157	0	00 08		165/2	0	22 00
	192	0	37 00		160	0	19 00
	193	0	14 00		159	0	34 00
	194	0	00 06		157	0	11 00
	191/1	0	30 00		156	0	09 00
	191/2	0	19 00		95	0	13 00
	185	0	72 00		103	0	16 00
	174/1	0	31 00		104	0	09 00
	179	0	27 00		105	0	28 00
	180	0	36 00		106	0	35 00
वेडा	181पी/1	0	31 36		132	0	33 00
	181 पी/2	0	27 32		131	0	30 00
	180	0	44 52		130	0	29 00
	179	0	34 38		129	0	27 00
	178	0	27 32		126	0	18 00
	108	0	21 25				
	106	0	14 16				
	94	0	59 69				
मोटा बाबरिया	83	0	12 14	घालिया	138	0	08 00
	335	0	14 00		139/1	0	17 00
	336	0	35 00		139/2	0	08 00
	342	0	23 00		171	0	26 00
	324	0	40 00		170	0	20 00
	323	0	32 00		169	0	39 00
मोटा बाबरिया	319	0	47 00		168	0	17 00
	312	0	01 00		187	0	21 00
	316	0	33 00		165	0	34 00
	315	0	61 00		188	0	34 00
	400 पी	0	15 00		193	0	11 00
	305	0	39 00		191	0	47 55
	290	0	03 00		206	0	08 00
	291	0	31 00		258	0	01 00
	292	0	03 00		259	0	55 00
					284	0	59 64
					290	0	34 00
					291	0	27 33
					292	0	46 34

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
गंगाज ला	80	0 13 49		37 पी/1	0 29 90
मोडा	452	0 87 00		37 पी/2	0 30 54
	459	0 53 62		39/1	0 17 83
	465	0 03 36		39/2	0 30 00
	462	0 49 57	जामबनायली	75	0 16 00
	381/1	0 25 20		74 पी/1	0 03 00
	380	0 13 25		76	0 06 00
	379	0 20 00		77	0 18 00
	331/1	0 15 18		74 पी/2	0 15 00
	330	0 13 15	जामबनायली	81	0 17 00
	329	0 06 07		82	0 36 00
	332	0 02 02		83	0 38 00
	333	0 05 06		84	0 07 00
	328	0 25 29		108	0 19 00
	326/1	0 14 16		107	0 05 00
	324	0 04 05		106	0 19 00
	325	0 31 36		122	0 10 00
	321	0 46 54		121	0 19 00
	483/पी/1	0 18 21		132	0 34 00
मोडा	483/पी/2	0 22 26		136	0 08 00
	316	0 27 32		135	0 12 00
	317	0 44 52		138	0 27 00
	223	0 24 28		139	0 37 00
	221	0 30 35	न माधान	190	0 29 00
	220/पी/1	0 17 20	वीरवार	139	0 46 00
	220/पी/2	0 16 19		136	0 02 00
	215	0 32 37		138	0 25 00
	205	0 23 27		137	0 08 00
	208	0 46 54		134	0 16 00
	207	0 22 26		133	0 55 00
	201	0 27 32		88	0 20 00
	197	0 39 46		89	0 18 00
	194/पी/1	0 17 20		90	0 14 00
	194/पी/2	0 24 28		84	0 18 00
	193	0 20 23		91	0 08 00
	191	1 24 44		92	0 32 00
	147	0 27 32		81	0 21 00
	148	0 33 39		80	0 56 00
	150	0 38 45		79	0 15 00
	152	0 41 48		78	0 36 00
बावडा	73	0 28 62		76	0 32 00
	71	0 27 43		61	0 23 00
	70	0 06 22		62	0 37 00
	68	0 18 11		64	0 58 00
	66	0 25 24		65	0 45 00
	63/2	0 23 14		66	0 65 00
	48/2	0 29 54			
	49/2	0 37 03			

[संख्या 12017/3/74-एल तथा एल/X]

पी० पी० गुप्ता, उप सचिव

S. O. 3030.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation, Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

[No 120 17/3/74/ L & L/X]

SCHEDULE

Taluka: Jamnagar District: Jamnagar
Gujarat State

Village	Survey No.	H.	Extent A.	Sq. M.
MORKANDA	231	0	15	00
	216	0	16	00
	213	0	35	00
	212	0	05	00
	142	0	26	00
	143/2	0	07	00
	144	0	09	00
	145/1	0	22	00
	145/2	0	18	00
	156	0	55	00
	157	0	00	08
	192	0	37	00
	193	0	14	00
	194	0	00	06
	191/1	0	30	00
	191/2	0	19	00
	185	0	72	00
	174/1	0	31	00
	179	0	27	00
	180	0	36	00
THEBA	181 P/1	0	31	36
	181 P/2	0	27	32
	180	0	44	52
	179	0	34	36
	178	0	27	32
	108	0	21	25
	106	0	14	16
	94	0	59	69
	83	0	12	14

1	2	3
MOTA THAVARIA	335	0 14 00
	336	0 35 00
	342	0 23 00
	324	0 40 00
	323	0 32 00
	319	0 47 00
	312	0 01 00
	316	0 33 00
	315	0 61 00
	400 P	0 15 00
	305	0 39 00
	290	0 03 00
	291	0 31 00
	292	0 03 00
	293	0 11 00
	278	0 16 00
	265	0 27 00
	276	0 04 00
	277	0 16 00
	275	0 28 00
	267	0 06 00
	208	0 27 00
	206	0 14 00
	164/1	0 23 00
	164/2	0 13 00
	164/3	0 15 00
	165/1	0 28 00
	165/2	0 22 00
	160	0 19 00
	159	0 34 00
	157	0 11 00
	156	0 09 00
	95	0 13 00
	103	0 16 00
	104	0 09 00
	105	0 28 00
	106	0 35 00
ALIA	132	0 33 00
	131	0 30 00
	130	0 29 00
	129	0 27 00
	126	0 18 00
	138	0 08 00
	139/1	0 17 00
	139/2	0 08 00
	171	0 26 00
	170	0 20 00
	169	0 39 00
	168	0 17 00
	187	0 21 00
	165	0 34 00
	188	0 34 00
	193	0 11 00
	191	0 47 55
	206	0 08 00
	258	0 01 00

1	2	3	1	2	3
ALLIA (Contd.—)	259	0 55 00	JAMVANATHALI	75	0 16 00
	284	0 54 64		74 P/1	0 03 00
	290	0 34 40		76	0 06 00
	291	0 27 33		77	0 18 00
	292	0 54		74 P/2	0 15 00
GANGAJALA	80	0 13 49		81	0 17 00
NODA	452	0 87 00		82	0 36 00
	459	0 53 62		83	0 38 00
	465	0 03 36		84	0 07 00
	462	0 49 57		108	0 19 00
	381/1	0 25 29		107	0 65 00
	380	0 13 25		106	0 19 00
	379	0 20 00		122	0 10 00
	331/1	0 15 18		121	0 19 00
	330	0 13 15		132	0 34 00
	329	0 06 07		136	0 08 00
	332	0 02 02		135	0 12 00
	333	0 05 06		138	0 27 00
	328	0 25 29		139	0 37 00
	326/1	0 14 16	TAMACHAN	190	0 29 00
	324	0 04 05	VIRPAR	139	0 46 00
	325	0 31 36		136	0 02 00
	321	0 46 54		138	0 25 00
	483 P/1	0 18 21		137	0 08 00
	483 P/2	0 22 26		134	0 16 00
	316	0 27 32		133	0 55 00
	317	0 44 52		88	0 20 00
	223	0 24 28		89	0 18 00
	221	0 30 35		90	0 14 00
	220 P/1	0 17 20		84	0 18 00
	220 P/2	0 16 19		91	0 08 00
	215	0 32 37		92	0 32 00
	205	0 23 27		81	0 21 00
	206	0 46 54		80	0 56 00
	207	0 22 26		79	0 15 00
	201	0 27 32		78	0 36 00
	197	0 39 46		76	0 32 00
	194 P/1	0 17 20		61	0 23 00
	194 P/2	0 24 28		62	0 37 00
	193	0 20 23		64	0 58 00
	191	1 24 44		65	0 45 00
	147	0 27 32		66	0 65 00
	148	0 33 39			
	150	0 38 45			
	152	0 41 48			
CHAVDA	73	0 28 62			
	71	0 27 43			
	70	0 06 22			
	68	0 18 11			
	66	0 25 24			
	63/2	0 23 14			
	48/2	0 29 54			
	49/2	0 37 03			
	37 P/1	0 29 90			
	37 P/2	0 30 54			
	39/1	0 17 83			
	39/2	0 30 00			

[No. 12017/3/74-L&L/X]

का० प्र० 3031.—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पलत से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत्: ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रजित करना आवश्यक है :

प्रतः, अथ, पट्टोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राणय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हिलब्रड कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लि०, सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "बोली"-33 बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : जामनगर	जिला : जामनगर	गुजरात-राज्य		
ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र		
		एक	ए	वर्ग मीटर
1	2	3		
मोती जाबरी	29 पी	0	12	32
	572	0	19	20
	25 पी/1	0	40	81
	25 पी/2	0	28	01
	21	0	16	67
	20	0	13	70
	19 पी/1	0	39	89
	19 पी/2	0	15	97
	46 पी	0	14	09
	15	0	49	78
	14	0	35	87
	10	0	30	01
	586	0	38	98
	602	0	31	66
	176/2	0	16	19
	176/1	0	26	33
	179	0	22	33
	249	0	29	51
	248	0	10	80
	250 पी	0	01	12
	247/1	0	30	52
	251/1	0	21	00
	252	0	14	14
	237	0	06	43
	128	0	05	44
	238	0	15	42
	239	0	03	48

1	2	3		
	240	0	08	21
	256	0	14	70
	257/1	0	33	12
	268	0	03	45
	269	0	42	83
	270	0	12	65
	371	0	05	03
	272	0	05	30
	277 पी	0	07	69
	278	0	11	80
	280	0	37	25
	283	0	00	63
	284	0	09	52
	285	0	18	90
	345	0	00	58
	347	0	21	59
	349/1	0	18	71
	344/पी/1	0	04	32
	344/पी/2	0	19	63
	344/पी/3	0	19	40
	344/पी/4	0	19	25
	322/पी	0	25	92
	342/पी	0	37	80
सापर	32	0	11	13
	33	0	04	05
	34	0	27	32
	69	0	20	23
	68	0	22	26
	74	0	51	60
	91/2	0	06	07
	90	0	16	19
	86	0	27	32
	84	0	40	48
	109	0	15	18
	124/1	0	29	32
भमरा	495	0	32	37
	494	0	24	27
	498	0	41	48
	499	0	23	28
	504	0	24	27
	501	0	16	19
	502	0	28	33
	503	0	12	15
	518	0	38	45
	519	0	08	10
	521	0	20	23
	517	0	01	01
	515	0	41	48
	514	0	09	11
	513	0	09	11

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ममर-जारी	581	0	02	02		214	0	23	00
	582	0	09	11		226	0	59	66
	583	0	21	25		229	0	27	32
	602	0	20	23		246	0	20	26
	63/1	0	18	21	नयेडी	1 पी	0	31	35
	58	0	16	19		187/पी/1	0	10	00
	67	0	28	33		187/पी/2	0	14	00
	3	0	08	09		4	0	04	05
	8	0	08	09		5	0	19	25
	7	0	17	20		7	0	23	30
	6	0	24	28		8	0	32	40
	11	0	02	02		11	0	07	05
	32	0	16	19		12 पी/1	0	36	35
	33	0	11	13		12 पी/2	0	18	25
	34	0	23	27	कनसुमारा	295	0	63	75
	35	0	26	30		299	0	13	20
	61	0	44	52		298	0	18	20
मसाई	17	0	22	26		8	0	26	30
	23/1	0	16	18		6/2	0	16	20
	23/2	0	52	61		6/3	0	07	00
	27	0	70	82		39	0	54	80
	28/2	0	52	61	कनसुमारा	40/2/1	0	21	30
	35	0	70	82		40/2/2	0	21	30
	36	0	22	26		69	0	14	20
	37/1	0	28	34		62	0	08	10
	37/2	0	44	51		63	0	33	40
	39/3	0	72	84		68	0	17	20
	39/2	0	09	10		67	0	17	20
	39/1	0	01	01		66	0	15	20
रवाभसर	2	0	24	00		73	0	27	40
	3 पी	0	22	26		74/पी/1	0	27	30
	57	0	09	11		74/पी/2	0	22	25
	54	0	05	06	जामनगर	1327	0	35	25
	53	0	08	09		1303	0	23	99
	60	0	10	12		1302	0	30	94
	61	0	20	23		1295	0	52	00
	62	0	36	00		1199	0	15	75
	64	0	20	27		1227	0	11	17
लखा बावल	129/1	0	11	13		1200 पी/1	0	45	19
	129/2	0	08	09		1200 पी/2	0	16	01
	129/3	0	27	32		1211	0	04	41
	129/4	0	22	26		1210	0	04	16
	129/5	0	25	29		1207	0	02	16
	129/6	0	63	74		1208	0	49	56
	128	0	21	00		1209	0	10	99
	143	0	29	43		1205	0	32	96
	146	0	34	40		1115	0	26	00
	148	0	39	46		1116	0	09	89
	168	0	58	68		1126	0	10	40
	172	0	04	05		1124	0	25	45
	213	0	37	42		973	0	06	41

1	2	3	4	5
जाम नगर-जारी	974	0	23	07
	980	0	28	38
	981	0	28	38
	1014	0	39	18
	1016	0	36	07
	1017	0	18	49
	788/1	0	32	96
	753	0	79	47
	715	0	88	97

[संख्या 12017/3/74-एन० तथा एन०/XI]

S.O. 3031.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka:Jamnagar District:Jamnagar Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2	3		
Moti Khavdi	29 P.	0	12	32
	572	0	19	20
	25 P/1	0	40	81
	25 P/2	0	28	01
	21	0	16	67
	20	0	13	70
	19 P/1	0	39	89
	19 P/2	0	15	97
	46 P	0	14	09
	15	0	49	78
	14	0	35	27
	10	0	30	01
	586	0	38	98
	602	0	31	66
	176/2	0	16	19
	176/1	0	26	35
	179	0	22	33
	249	0	29	51
	248	0	10	80
	250 P.	0	01	12

1	2	3		
Moti Khavdi (Contd.)	247/1	0	30	52
	251/1	0	21	00
	252	0	14	14
	237	0	06	43
	128	0	05	44
	238	0	15	42
	239	0	03	48
	240	0	08	21
	256	0	14	70
	257/1	0	33	12
	268	0	03	45
	269	0	42	85
	270	0	12	65
	271	0	05	03
	272	0	05	30
	277 P.	0	07	69
	278	0	11	80
	280	0	37	25
	283	0	00	63
	284	0	09	52
	285	0	18	90
	345	0	00	58
	347	0	21	59
	349/1	0	18	71
	344 P/1	0	04	32
	344 P/2	0	19	63
	344 P/3	0	19	40
	344 P/4	0	19	25
	322 P.	0	25	92
	342 P.	0	37	80
Sapar	32	0	11	13
	33	0	04	05
	34	0	27	32
	69	0	20	23
	68	0	22	26
	74	0	51	60
	91/2	0	06	07
	90	0	16	19
	86	0	27	32
	84	0	40	48
Amra	109	0	15	18
	124/1	0	29	32
	495	0	32	37
	494	0	24	27
	498	0	41	48
	499	0	23	28
	504	0	24	27
	501	0	16	19
	502	0	28	33
	503	0	12	15
	518	0	38	45
	519	0	08	10
	521	0	20	23
	517	0	01	01
	515	0	41	48
	514	0	09	11
	513	0	09	11
	581	0	02	02
	582	0	09	11
	583	0	21	25

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Amra (contd.)	602	0	20	23		11	0	07	05
	63/1	0	18	21		12P/1	0	36	35
	68	0	16	19		12P/2	0	18	25
	67	0	28	33	Kansumara	295	0	63	75
	3	0	08	09		299	0	13	20
	8	0	08	09		298	0	18	20
	7	0	17	20		8	0	26	30
	6	0	24	28		6/2	0	16	20
	31	0	02	02		6/3	0	07	00
	32	0	16	19		39	0	54	80
	33	0	11	13		40/2/1	0	21	30
	34	0	23	27		40/2/2	0	21	30
	35	0	26	30		69	0	14	20
	61	0	44	52		62	0	08	10
Vasai	17	0	22	26		63	0	33	40
	25/1	0	16	18		68	0	17	20
	25/2	0	52	61		67	0	17	20
	27	0	70	82		66	0	15	20
	28/2	0	52	61		73	0	27	40
	35	0	70	82		74P/1	0	27	30
	36	0	22	26		74P/2	0	22	25
	37/1	0	28	34	Jambagar	1327	0	35	25
	37/2	0	44	51		1303	0	23	99
	39/3	0	72	84		1302	0	30	94
	39/2	0	09	10		1295	0	52	00
	93/1	0	01	01		1199	0	15	75
Ravalsar	2	0	24	00		1227	0	11	17
	3P.	0	22	26		1200P/1	0	45	19
	57	0	09	11		1200P/2	0	16	01
	54	0	05	06		1211	0	04	41
	53	0	08	09		1210	0	04	16
	60	0	10	12		1207	0	02	16
	61	0	20	23		1208	0	49	56
	62	0	36	00		1209	0	10	99
	64	0	20	27		1205	0	32	96
Lakha Baval	129/1	0	11	13		1115	0	26	00
	129/2	0	08	09		1116	0	09	89
	129/3	0	27	32		1126	0	10	40
	129/4	0	22	26		1124	0	25	45
	129/5	0	25	29		973	0	06	41
	129/6	0	63	74		974	0	23	07
	128	0	21	00		980	0	28	38
	143	0	29	43		981	0	28	38
	146	0	34	40		1014	0	39	18
	148	0	39	46		1016	0	36	07
	168	0	58	68		1017	0	18	49
	172	0	04	05		788/1	0	32	96
	213	0	37	42		753	0	79	47
	214	0	23	00		745	0	86	97
	226	0	59	66					
	229	0	27	32					
	246	0	20	26					
Naghedi	1P.	0	31	35					
	187P/1	1	10	00					
	187P2	0	14	00					
	4	0	04	05					
	5	0	19	25					
	7	0	23	30					
	8	0	32	40					

[No. 12017/3/74-L&L/XI]

क्र० घा० 3032.---यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित से यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यन ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

धतः धन, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजनन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लि० सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली" 33-बी०, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिवृत्तना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

अनुसूची

तालुका: सयाला	जिला: सुरेन्द्रनगर	गुजरात राज्य		
ग्राम	सर्वेक्षण सं०	एक	भेज ग	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
धरादुंगरी	115	0	40	47
	114	0	04	05
	116	0	08	09
	117	0	22	26
	80	0	37	43
	78	0	35	41
	76	0	39	46
	74	0	24	28
	143	0	11	13
	178	0	35	42
हडाला	172	0	53	62
	161	0	59	69
	35	4	44	14
	34	1	98	30
सीतागढ़	18	0	17	20
सोरीभदा	75	0	07	08
	76	0	17	20
	78	0	34	40
	82	0	03	04
	50	0	02	02
	48	0	25	29
	49	0	13	15
कानपुर	91	0	40	47
	92	0	72	84
	87	0	34	40
	66	0	16	19
	42	0	41	48
	41	0	02	03
	40	0	30	35
	20	0	42	49
	22	0	56	65
	24	0	09	11
	31	0	37	47

1	2	3	4	5
चोरखीर (धान०)	456 पी०/1	0	13	15
	456 पी०/2	0	18	21
	457	0	30	35
	458/1 पी०	0	18	21
	460 पी०/1	0	15	18
	460 पी०/2	0	08	09
	461	0	23	27

[सं० 12017/3/74-एस० तथा एस० /3]

S. O. 3032.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Harihar Society, Rajkot.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE.

Taluka:- Siyala District: Surendranagar Gujarat State.

Village.	Survey No.	Extent. H. A. Sq. M.		
1	2	3	4	5
DHARADUNGARI	115	0	40	47
	114	0	04	05
	116	0	08	09
	117	0	22	26
	80	0	37	43
	78	0	35	41
	76	0	39	46
	74	0	24	28
	143	0	11	13
	178	0	35	42
HADALA	172	0	53	62
	161	0	59	69
	35	4	44	14
	34	1	98	30
SITAGADH	18	0	17	20
SORIMBHADA	75	0	07	08
	76	0	17	20
	78	0	34	40
	82	0	03	04
	50	0	02	02
	48	0	25	29
	49	0	13	15

1	2	3	4	5
KANPUR	91	0	40	47
	92	0	72	84
	87	0	34	40
	66	0	16	19
	42	0	41	48
	41	0	02	03
	40	0	30	35
	20	0	42	49
	22	0	56	65
	24	0	09	11
	31	0	37	47
CHORVIRA (THAN.)	456 P/1	0	13	15
	456 P/2	0	18	21
	457	0	30	35
	458 /1 P	0	18	21
	460 P/1	0	15	18
	460 P/2	0	08	09
	461	0	23	27

[No. 12017/3/74-L&L/III]

क्र० प्र० 3033.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय तेल निगम लि० सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली" 33-बी, हरिहर सोसायटी राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : खंभालिया	जिला : जामनगर	गुजरात राज्य		
ग्राम	सर्वेक्षण सं०	एच ए	क्षेत्र	बर्ग मीटर
वदिनार	68/1	0	54	04
	67	0	16	94
	66	0	00	52

[संख्या 12017/3/74-एल० तथा एल०/2]

S. O. 3033.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka: Khambhalia District: Jamnagar Gujarat State

Village	Survey No.	Extent	
		H.A.	Sq. M
VADINAR	68/1	0	54 04
	67	0	16 94
	66	0	00 52

[No. 12017/3/74-L&L/II]

क्र० प्र० 3034.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लि०, सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली" 33-बी, हरिहर सोसायटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची					1	2	3	4	5	
तालुका : मासार	जिला : बेड़ा	गुजरात राज्य			संभना	845/8	0	00	32	
ग्राम	सर्वेक्षण सं०	एक	भेदा	बर्ग		845/7	0	06	88	
		ए	मीटर			845/6	0	08	48	
1	2	3	4	5		845/9	0	00	08	
						845/5	0	07	20	
संभना	341/1	0	01	76		845/1	0	01	73	
	541/2	0	20	64		849/4	0	13	30	
	542	0	06	72		849/3	0	15	52	
	543/ए	0	05	12		848	0	16	80	
	543/4	0	05	12		847/3	0	00	64	
	543/3	0	11	52		857/2	0	06	72	
	543/2	0	01	00		868/ए०	0	01	92	
	562/1	0	16	00		869	0	08	64	
	562/2	0	10	40		870	0	16	74	
	563	0	21	92		872	0	10	70	
	569	0	00	32		873	0	12	48	
	619	0	02	88		874	0	12	32	
	618	0	13	60		875/1	0	14	26	
	610	0	02	56		876/1	0	07	20	
	616+617	0	11	36	हेवराबाद	3/3	0	15	20	
	611	0	20	48		3/1	0	05	28	
	679/1	0	14	40		16/1	0	00	32	
	675/4	0	05	44		6/3	0	10	56	
	678	0	07	94		6/2	0	00	16	
	677/1	0	00	96		6/1	0	13	28	
	677/2	0	11	36		5	0	01	60	
	694/7	0	12	00		7/3	0	05	76	
	694/6	0	08	80		7/2	0	04	00	
	694/4	0	03	68		7/1	0	09	28	
	695	0	13	76		8/1+2	0	01	92	
	697	0	00	80		11	0	00	20	
	696	0	10	44		9	0	11	84	
	783	0	00	32		57/2	0	00	48	
	782/8	0	02	88		57/1	0	10	88	
	782/7	0	12	64		55/2	0	02	88	
	782/6	0	03	52		56/2	0	00	80	
	782/3	0	16	00		56/1	0	06	08	
	782/2	0	00	08		51/1	0	09	60	
	781/बी०-3	0	04	61		68	0	00	20	
	781/बी०-2	0	10	56		69/5	0	00	16	
	781	0	08	48		69/4	0	00	04	
	794	0	00	80		70/1+2	0	01	92	
	780	0	01	01		71/1	0	09	12	
	779/1	0	18	56		71/2	0	06	88	
	779 पवतार	0	13	92		72/1+2	0	00	72	
	779/3	0	08	00		74	0	02	24	
	779/2	0	00	80		73	0	12	96	
	843/4	0	01	76		76	0	15	04	
	843/5	0	19	32		77/4	0	07	52	
	844/5	0	24	00						
	853/1	0	02	56	अन्तरोली	49	0	12	32	
	852	0	17	60		47	0	00	20	

2	3	1	2	3
48	0 25 44		677/2	0 11 36
29	0 02 40		694/7	0 12 00
39	0 06 00		694/6	0 08 80
38	0 08 80		694/4	0 03 68
30	0 14 40		695	0 13 76
27	0 04 80		697	0 00 80
25/3	0 00 80		696	0 10 44
26/2	0 12 00		783	0 00 32
26/1	0 00 20		782/8	0 02 88
22	0 15 00		782/7	0 12 64
24/1	0 06 88		782/6	0 03 52
23	0 15 00		782/3	0 16 00
			782/2	0 00 08
			781/B-3	0 04 61
			781/B-2	0 10 56
			781	0 08 48
			794	0 00 80
			780	0 01 01
			779/1	0 18 56
			779 Padtar	0 13 92
			779/3	0 08 00
			779/2	0 00 80
			843/4	0 01 76
			843/5	0 19 32
			844/5	0 24 00
			853/1	0 02 56
			852	17 60
			845/8	0 00 32
			845/7	0 06 88
			845/6	0 08 48
			845/9	0 00 08
			845/5	0 07 20
			845/1	0 01 73
			849/4	0 13 30
			849/3	0 15 52
			848	0 16 80
			847/3	0 00 64
			847/2	0 06 72
			868/A	0 01 92
			869	0 08 64
			870	0 16 74
			872	0 10 70
			873	0 12 48
			874	0 12 32
			875/1	0 14 26
			876/1	0 07 20

[संख्या 12018/3/74-एल० तथा एल०/1]

S. O. 3034.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto:

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its Intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka: Matar	District: Kheda	Gujarat State
Village	Survey No.	Extent H.A. Sq. M
1	2	3
SANDHANA	541/1	0 01 76
	541/2	0 20 64
	542	0 06 72
	543/A	0 05 12
	543/4	0 05 12
	543/3	0 11 52
	543/2	0 04 00
	562/1	0 16 00
	562/2	0 10 40
	563	0 21 92
	569	0 00 32
	619	0 02 88
	618	0 13 60
	610	0 02 56
	616+617	0 11 36
	611	0 20 48
	679/1	0 14 40
	675/4	0 05 44
	678	0 07 84
	677/1	0 00 96

HAJARABAD

3/3	0 15 20
3/1	0 05 28
16/1	0 00 32
6/3	0 10 56
6/2	0 00 16
6/1	0 13 28
5	0 01 60
7/3	0 05 76
7/2	0 04 00
7/1	0 09 28
8/1+2	0 01 92
11	0 00 20
9	0 11 84
57/2	0 00 48
57/1	0 10 88

1	2	3	4	5
HAIJARABAD (contd.)	55/2	0	02	88
	56/2	0	00	80
	56/1	0	06	08
	51/1	0	09	60
	68	0	00	20
	69/5	0	00	16
	69/4	0	00	04
	70/1+2	0	01	92
	71/1	0	09	12
	71/2	0	06	88
	72/1+2	0	00	72
	74	0	02	24
	73	0	12	96
	76	0	15	04
	77/4	0	07	52
ANTROLI	49	0	12	32
	47	0	00	20
	48	0	25	44
	29	0	02	40
	39	0	06	00
	38	0	08	80
	30	0	14	40
	27	0	04	80
	25/3	0	00	80
	26/2	0	12	00
	26/1	0	00	20
	22	0	15	00
	24/1	0	06	88
	23	0	15	00

[No. 12017/3/74-L&L/I]

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1974

का० आ० 3035.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी० जी० एम० सोभासण से दूध सागर डेरी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

2. और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

3. अतः, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का धर्जन) अधिनियम, 1982 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणव्य एन्ड द्वारा घोषित किया है।

4. बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप संक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोदा-9 को इस अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

5. और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिवृष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी जी एम सोभासण से दूध सागर डेरी तक पाइप लाइन बिछाने हेतु।

राज्य : गुजरात	जिला : सौराष्ट्र	तालुका : सौराष्ट्र	गांव	कलाक संख्या	हैक्टर	क्षेत्र	सेटी
						ए	आर ई आर ए
1	2	3	4	5	6	7	8
पूनासण	126	0	05	70			
	127	0	20	85			

1	2	3	4	5
	116	0	04	95
	115	0	04	20
	114	0	06	00
	113	0	05	85
हैबुआ	96	0	08	40
	100	0	10	35
	101	0	01	20
बैलगाड़ी का रास्ता		0	00	75
	99	0	23	25
	106	0	12	00
बैलगाड़ी का रास्ता		0	00	60
	109	0	35	05
	112	0	03	60
	119	0	00	20
	116	0	10	50
	117	0	08	10
	118	0	02	70
बैलगाड़ी का रास्ता		0	00	75
	166	0	12	30
बैलगाड़ी का रास्ता		0	00	75
	158	0	00	25
	165	0	20	55
	160	0	10	80
	288	0	01	12
	178	0	00	10
सोभासण	84	0	12	75
	83	0	03	45
	82	0	11	25
	81	0	10	50
बैलगाड़ी का रास्ता		0	00	75
	65	0	11	30
	66	0	12	30
	67	0	03	75
	69	0	00	10
	68	0	10	65
	64	0	03	75
	39	0	05	55
	60	0	04	65
	44	0	00	50
	45	0	08	40
	46/1/ए	0	04	35
	46/1/बी	0	06	00
	43	0	00	15
	47	0	11	70
बैलगाड़ी का रास्ता		0	00	90
	31	0	22	20
बैलगाड़ी का रास्ता		0	04	50
	29	0	08	85
कुक्स	276	0	08	70
	283	0	39	60
	289	0	17	20

1	2	3	1	2	3
	290	0 08 10		347/4	0 01 35
	303	0 19 35		347/3	0 01 95
	301	0 12 45		347/2	0 05 10
	302	0 03 15		347/1	0 01 50
	296	0 09 45		362	0 01 50
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 02 25		बैलगाड़ी का रास्ता	0 04 50
	295	0 05 25		261	0 00 60
हेरवा हनुमन्त	38	0 25 65		262	0 20 25
	42	0 00 20		250	0 09 90
	47	0 12 70		249	0 06 60
	46	0 12 90		228/1	0 13 05
	45	0 00 32		229/5	0 07 80
	43	0 02 25		230/6	0 07 50
	44/2	0 23 55		230/5	0 08 10
	44/1	0 07 95		230/2	0 14 25
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 30		230/1	0 00 20
	60	0 00 15		232	0 07 95
	62	0 25 50		बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 75
	67	0 12 00		184	0 09 30
	66	0 01 50		185/2	0 11 40
	68	0 32 25		186	0 09 30
	69	0 00 30		188	0 11 40
	71	0 08 40		168	0 11 85
	147	0 11 55		167	0 06 30
	148/2	0 01 04		32/2	0 12 30
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 01 05		बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 30
	230	0 27 90		33/2	0 08 40
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 01 05		51	0 00 30
	233	0 14 25		50	0 07 20
	234	0 00 80		61	0 09 30
	238	0 25 05		57	0 04 35
	खारी नदी	0 12 75		58	0 09 00
नागलपुर	मर्चक्षण संख्या			59	0 00 15
	खारी नदी	0 12 75		146	0 04 95
	412	0 03 00		145	0 08 00
	440/2	0 06 90		144	0 00 85
	441	0 01 50		74	0 09 00
	439	0 23 10		75	0 00 60
	438/1	0 07 95		76	0 16 00
	427	0 00 15		77	0 02 00
	428/2	0 12 75		133	0 00 60
	432	0 03 75		132	0 15 60
	430/2	0 12 45		131	0 03 15
	430/1	0 12 00		बैलगाड़ी का रास्ता	0 01 20
	429	0 00 96		120	0 00 50
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 01 50		121	0 19 80
	359	0 00 72		122	0 02 70
	361	0 10 95		114	0 05 85
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 75		111	0 10 80
				110	0 01 20
				बिमान पत्तन	0 20 55

1	2	3	4	5
मैहसाना	1919	0	01	50
	1906	0	12	60
	1907	0	05	85
	1908	0	15	60
	1909	0	08	40
	1915	0	02	55
	1914	0	09	00
	1911	0	04	50
	1912	0	04	50
	1830	0	17	10
	1851	0	06	00

[ए० 12016/13/74 एल एण्ड एल]

(पी० पी० गुप्ता, उपसचिव)

New Delhi, the 7th November, 1974

S.O. 3035.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G. G. S. Sobhasan to Dudh Sagar Dairy in Mehsana oil field Pipelines should be laid by the oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Laying Pipeline from GGS Sobhasan to Dudh Sagar Dairy
State:Gujarat District:Mehsana Taluka:Mehsana

Village	Block No.	Hec- tare	Area Are	Cent- teare
1	2	3	4	5
Punasan	126	0	05	70
	127	0	20	85
	116	0	04	95
	115	0	04	20
	114	0	06	00
	113	0	05	85
Hebuva	96	0	08	40
	100	0	10	35
	101	0	01	20
	Cart track	0	00	75
	99	0	23	25
	106	0	12	00
	Cart track	0	00	60
	109	0	35	05
	112	0	03	60
	119	0	00	20
	116	0	10	50

1	2	3	4	5
Hebuva	117	0	80	10
	118	0	02	70
	Cart track	0	00	75
	166	0	12	30
	Cart track	0	00	75
	158	0	00	25
	165	0	20	55
	160	0	10	80
	288	0	01	12
	178	0	00	10
Sobhasan	84	0	12	75
	83	0	03	45
	82	0	11	25
	81	0	10	50
	Cart track	0	00	75
	65	0	11	30
	66	0	12	30
	67	0	03	75
	69	0	00	10
	68	0	10	65
	64	0	03	75
	39	0	05	55
	60	0	04	65
	44	0	00	50
	45	0	08	40
	46/1/A	0	04	35
	46/1/B	0	06	00
	43	0	00	15
	47	0	11	70
	Cart track	0	00	90
	31	0	22	20
	Cart track	0	04	50
	29	0	08	85
Kukas	276	0	08	70
	283	0	39	60
	289	0	17	20
	290	0	08	10
	303	0	19	35
	301	0	12	45
	302	0	03	15
	296	0	09	45
	Cart track	0	02	25
	295	0	05	25
Hedva Hanmant	38	0	25	65
	42	0	00	20
	47	0	12	70
	46	0	12	90
	45	0	00	32
	43	0	02	25
	44/2	0	23	55
	44/1	0	07	95
	Cart track	0	00	30
	60	0	00	15
	62	0	25	50
	67	0	12	00
	66	0	01	50
	68	0	32	25
	69	0	00	30
	71	0	08	40
	147	0	11	55

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Hedva Hanmant—Contd	148/2	0	01	04		74	0	09	00
	Cart track	0	01	05		75	0	00	60
	230	0	27	90		76	0	16	00
	Cart track	0	01	05		77	0	02	00
	233	0	14	25		133	0	00	60
	234	0	00	80		132	0	15	60
	238	0	25	05		131	0	03	15
	Khari river	0	12	75		Cart track	0	01	20
	Survey No.					120	0	00	50
Nagalpur	Khari River	0	12	75		121	0	19	80
	442	0	03	00		122	0	02	70
	440/2	0	06	90		114	0	05	85
	441	0	01	50		111	0	10	80
	439	0	23	10		110	0	01	20
	438/1	0	07	95		Air port	0	20	55
	427	0	00	15	Mehsana	1919	0	01	50
	428/2	0	12	75		1906	0	12	60
	432	0	03	75		1907	0	05	85
	430/2	0	12	45		1908	0	15	60
	430/1	0	12	00		1909	0	08	40
	429	0	00	96		1915	0	02	55
	Cart track	0	01	50		1914	0	09	00
	359	0	00	72		1911	0	04	50
	361	0	10	95		1912	0	04	50
	Cart track	0	00	75		1830	0	17	10
	347/4	0	01	35		1851	0	06	00
	347/3	0	01	95					
	347/2	0	05	10					
	347/1	0	01	50					
	362	0	01	50					
	Cart track	0	04	50					
	261	0	00	60					
	262	0	20	26					
	250	0	09	90					
	249	0	06	60					
	228/1	0	13	05					
	229/5	0	07	80					
	230/6	0	07	50					
	230/5	0	08	10					
	230/2	0	14	25					
	230/1	0	00	20					
	232	0	07	95					
	Cart track	0	00	75					
	184	0	09	30					
	185/2	0	11	40					
	186	0	09	30					
	188	0	11	40					
	168	0	11	85					
	167	0	06	30					
	32/2	0	12	30					
	Cart track	0	00	30					
	33/2	0	08	40					
	51	0	00	30					
	50	0	07	20					
	61	0	09	30					
	57	0	04	35					
	58	0	09	00					
	59	0	00	15					
	146	0	04	95					
	145	0	08	00					
	144	0	00	85					

[No. 12016/13/74-L&L]

P. P. GUPTA, Deputy Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1974

का० प्रा० 3036.—डाक कर्मकार (विनियोजन का विनियमन)
अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उपधारा (3)
और (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा श्री के० के० उप्पल के स्थान पर श्री जे० सी० अग्रवाल को
बम्बई गोदी श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उन्हें बोर्ड का
अध्यक्ष मनोनीत करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार
और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना
सं० का० प्रा० 3912 तारीख 20 नवम्बर, 1970 से और आगे निम्न-
लिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

(क) "केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्ष के
अन्तर्गत सब संख्या (1) के लिये निम्नलिखित मद रखे जायेंगे
अर्थात्—

"(1) श्री जे० सी० अग्रवाल, अध्यक्ष, बम्बई पत्तन न्यास
—अध्यक्ष"

(ख) पैरा 2 के लिए निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात्—

"(2) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे० सी० अग्रवाल को
उक्त बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करती है।"

[सं० 51/5/68-कार 11/पी एण्ड डी]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 31st October, 1974

S.O. 3036.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers Regulation of Employment Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri J. C. Agarwal to be a member of the Bombay Dock Labour Board, *vice* Shri K. K. Uppal and nominates him to be the Chairman of that Board and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3912, dated the 20th November, 1970 namely :—

(a) under the heading "members representing the Central Government", for item (i), the following item shall be substituted, namely :—

"(1) Shri J. C. Agarwal, Chairman, Bombay Port TrustChairman"

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"(2) The Central Government hereby nominates Shri J. C. Agarwal as the Chairman of the said Board."

[No. 51/5/68-Fac. II/P&D]

का० आ० 3037.—कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त उपधारा द्वारा यथापेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनका उमरसे प्रभावित होना सम्भाव्य है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्राप्त किए जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्कीम का प्रारूप

1.—इस स्कीम का नाम कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1974 है।

2.—कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में,—

(i) खण्ड 18 के अपखण्ड (i) की मद (ग) में, "60 वर्ष" शब्दों और शब्द के स्थान पर "58 वर्ष" शब्द और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड 18-क के परन्तुक में, "ऐसा कोई कर्मकार", शब्दों के पश्चात् "जिसने 21 जुलाई, 1972 से पूर्व सेवा में प्रवेश किया हो" शब्द और शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[एम्-70012/9/74-एल डी]

S.O. 3037.—The following draft of a Scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period

so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1974.

2. In the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959—

(i) in item (c) of sub-clause (1) of clause 18, for the figures and word "60 years" the figures and word "58 years" shall be substituted;

(ii) in the proviso to clause 18A, after the words, "such a worker" the words, figures and letters "who had joined service prior to 21st July, 1972" shall be inserted.

[No. S-70012/9/74/LD]

का० आ० 3038.—यतः कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप स्कीम, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, अपखण्ड (ii) तारीख 8 जून, 1974 के पृष्ठ 1499 पर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1404, तारीख 27 मई, 1974 के अधीन प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उमरसे प्रभावित होना सम्भाव्य था, आक्षेप और सुझाव राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक आमन्त्रित किए गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 8 जून, 1974 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप पर जनता की ओर से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इस स्कीम का नाम कलकत्ता डॉक (नियोजन का विनियमन) पाँचवाँ संशोधन स्कीम, 1974 है।

(2) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में, अनुसूची 1 में, पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थातः—

"(1) नौभरण कार्य, जिसमें नमक (कोयला नौभरण, कोयला बंकरिंग, यात्री-सामान और डॉक-कार्य से भिन्न) भी सम्मिलित है।

[सं० एम्-70012/11/73-पी एण्ड डी/एल डी]

S.O. 3038.—Whereas certain draft scheme further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1499-1500 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 8th June, 1974 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 1404 dated the 27th May, 1974 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 8th June, 1974 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, namely :—

1. Short title and commencement—(1) This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Fifth Amendment Scheme, 1974.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, in Schedule I, for paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely :—

“(1) Stevedoring work, including salt, (other than coal stevedoring, coal bunkering, passenger baggages and mail work).”

[No. S-70012/11/73-P&D/LD]

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

का० आ० 3039.—डाक कर्मकार (नियोजक का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 ए की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा काङ्गला पत्तन न्याय के अध्यक्ष श्री एन० पी० बापत की काङ्गला डाक श्रम बोर्ड का संवस्य नियुक्त करती है और उन्हें कप्तान श्री० बी० सिंह के स्थान पर उक्त बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्रम एवं रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० सा० आ० 3805, दिनांक 26 अक्टूबर, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में

(I) “केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले संवस्य” शीर्ष के अन्तर्गत प्रविष्टि (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए; अर्थात् :—

“(i) श्री एन० पी० बापत, अध्यक्ष, काङ्गला पत्तन न्याय गांधी धाम”,

(ii) पैरा 2 में “कप्तान श्री० बी० सिंह” शब्द तथा प्रक्षर के स्थान पर “एन पी० बापत” शब्द तथा प्रक्षर रखे जाएँ।

[सं० बी-17012/1/72-एन डी]

New Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3039.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers

(Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri N. P. Bapat, Chairman, Kandla Port Trust as a member of the Kandla Dock Labour Board and nominates him as the Chairman of the said Board vice Captain D. V. Singh and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Deptt. of Labour and Employment) No. S.O. 3805 dated the 25th October, 1968, namely :—

In the said notifications,

(i) Under the heading “Members representing the Central Government”, for entry (i) the following shall be substituted namely :—

“(i) Shri N. P. Bapat, Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham”,

(ii) In paragraph 2, for the words and letters “Capt. D. V. Singh” the words and letters “Shri N. P. Bapat” shall be substituted.

[No. V-17012/1/72-LD]

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

का० आ० 3040.—डाक कर्मकार (नियोजक का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उपधाराओं (3) और (4) के साथ पठित धारा 6-अ की उपधारा (3) के खड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० पी० एम्बोज, अध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्याय को श्री आर० बाबुसुब्रह्मण्यम् की जगह अध्यक्ष मद्रास गोदी श्रम बोर्ड नियुक्त करने है और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 169 (ई) दिनांक 25 फरवरी 1972 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना में,—

(क) “केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि संवस्य” शीर्ष के अन्तर्गत मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—
“(1) श्री एम० पी० एम्बोज, अध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्याय”
--- अध्यक्ष

(ख) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“2. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० पी० एम्बोज, अध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्याय, मद्रास को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।”

(सं० बि-15012/1/73/पी०एनड डी०/एल०डी०)

बी० शर्करासिंह, प्रवर सचिव

New Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3040.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 6B read with sub-section (3) and (4) of section 5A, of the Dock Workers (Re-

gulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri S. P. Ambrose, Chairman, Madras Port Trust as Chairman, Madras Dock Labour Board vice Shri R. Balasubramanian and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Deptt. of Labour and Employment) No. S.O. 169(E), dated the 25th February, 1972, namely :—

In the said notification—

(a) under the heading "Members representing the Central Government" for item (1), the following item shall be substituted, namely :—

"(1) Shri S. P. Ambrose, Chairman, Madras Port Trust"—Chairman.

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"(2) The Central Government hereby nominates Shri S. P. Ambrose, Chairman, Madras Port Trust, Madras as Chairman of the said Board."

[No. V-15012/1/73/P&D/LD]
V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1974

क्रा०प्रा० 3041.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना क्रा० प्रा० सं० 255(ई) दिनांक 2 मई, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के मद (ix) में "सर्वस्य लोक सभा" शब्द हटा दिये जाय।

[सं० 15-डी ए जी (35)/73]
एन० ए० ए० नारायणन, अवर सचिव,

New Delhi, the 4th November, 1974

S.O. 3041.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S. O. No. 255 (E), dated the 2nd May, 1973, namely :—

In item (ix) of the said notification, the words "Member, Lok Sabha" shall be omitted.

[No. 15-TAG(35)/73]
N. A. A. NARAYANAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1974

क्रा०प्रा० 3042.—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा (1) श्री गुणेंद्र नाथ राय तथा (2) श्री शंकर गुप्ता औषधि निरीक्षक केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, पूर्वी जोन, कलकत्ता और (3) श्री इन्द्रजी महगल, औषधि निरीक्षक, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन उत्तरी जोन, गाजियाबाद को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

[सं० 11031/8/73-डी० एण्ड एम०एस०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 9th October, 1974.

S.O. 3042.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) the Central Government hereby appoints (1) Shri Gunendra Nath Ray and (2) Shri Shankar Gupta, Drugs Inspectors, Central Drugs Standard Control Organisation, East Zone, Calcutta and (3) Shri Inderjit Sehgal, Drugs Inspector, Central Drugs Standard Control Organisation, North Zone, Ghaziabad, as Inspectors for the purposes of the said Act for the whole of India.

[No. 11031/8/73-D&MS]

क्रा०प्रा० 3043.—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए और आगामी आवेशों तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के अन्दर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 33B, 33C, 33D, और 33E के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे।

[सं० 11035/34/74-डी एण्ड एम एस]

सती नायर, अवर सचिव

S.O. 3043.—In pursuance of the clause (1) of article 239 of the constitution the President hereby directs that the Lieutenant Governor of Delhi and Chief Commissioner, the Andaman and Nicobar Islands, Goa, Daman and diu, Pandicherry shall subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of State Government under Section 33D, 33E, 33F and 33G of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), within their respective Union territories.

[No. 11035/34/74-D&MS]

MRS. SATHI NAIR, Under Secy.

रूढ़ि मंत्रालय

(जाति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1974

क्रा०प्रा० 3044.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फल-उत्पाद आदेश, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1 इस आदेश का नाम फल-उत्पाद (संशोधन) आदेश, 1974 है।

2 फल उत्पाद आदेश, 1955 की द्वितीय अनुसूची में, भाग 22 में,

(क) पैरा 2 और तदधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् —

“(2) ऐसे कोलतार रजक, जो उपयोग में लाये जा सकें— निम्न-लिखित के सिवाय, किसी कोलतार रजक या उसके मिश्रण का उपयोग फल-उत्पादों में नहीं किया जायेगा —

रंग	सामान्य नाम	रंग अनुक्रम-संख्या	रसायन-वर्ग
		(1956)	
लाल	पानसिन्धो 4 आर	16255	ऐजो
	कारमोइसीन	14720	”
	फास्ट रेड ई	16045	”
	ऐमैरंथ	16185	”
	ऐरीथ्रोसीन	45430	ऐथीन
पीन	टैटारजिन	19140	पिराजोलोन
	सनसेट यलो एफ सी एफ	15985	ऐजो
नीला	इंडिगो कार्मीन	73015	इन्डिगोइड
	ब्रिलिएण्ट ब्लू	42090	ट्रायरिलमेथेन
हरा	ग्रीन एस	44090	ट्रायरिलमेथेन
	फास्ट ग्रीन	42033	”
	एफ सी एफ		

(ख) पैरा (3) में, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

“केवल वही अनुज्ञात कोलतार रंग, जो भारतीय मानक संस्था प्रमानन बिन्दु के अधीन बेचे जाते हैं, फल उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग में लाए जाएंगे ”।

[सं० 9(4)/7-एफ०एन०बी० 4]

आर० एम० मरीन, सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi 20th October, 1974

S O, 3044—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fruit Products Order 1955 namely:—

1 This Order may be called the Fruit Products (Amendment) Order, 1974

2 In the Second Schedule to the Fruit Products Order, 1955, in Part XXII,

(a) for paragraph (2) and the Table thereunder, the following shall be substituted, namely:—

(2) Coal tar dyes which may be used—No Coal tar dyes or a mixture thereof except the following shall be used in fruit products:—

Colour	Common name	Colour Index	Chemical class
		(1956)	
Red	Ponceau 4R	16255	Azo
	Carmoisine	14720	”
	Fast Red F	16045	”
	Amaranth	16185	”
	Erythrosine	45430	Xanthene
Yellow	Tartarazine	19140	Pyrazolone
	Sunset Yellow FCF	15985	Azo
Blue	Indigo Carmine	73015	Indigoid
	Brilliant blue FCF	42090	Triarylmethane
Green	Green S	44090	-do-
	Fast Green FCF	42033	-do-

(b) in paragraph (3), the following shall be added at the end, namely:—

“only those permitted coal tar colours, which are sold under the Indian Standards Institution Certification Mark shall be used in the manufacture of fruit products”

[No 9(4)73-FNB IV]

R S SARIN, Under Secy

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd November, 1974

S.O. 3045.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad-I, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh), and their workmen which was received by the Central Government on the 30th October, 1974

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No 74 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Collieries.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Collieries

Appearances:—

Sri M Komarajah, General Secretary, S C Workers Union, for Workmen

Sri V Gopal Sastry, Asst Personnel Officer, S C Co Ltd. Kothagudem, for Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) through Notification No L/2112/25/71 LRII dated 22-10-1971 referred the industrial dispute between the Employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their Workmen, under Section 10(1)(d) and Section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (which would hereinafter be called the Act) for adjudication by the Tribunal on the following issue:—

"Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited in not granting Category-V wages to Sarvasri Sk. Masthan, Noorul Rahiman, M. Dharma Raj, T. Venkateswailu and Sofi Welders, is justified, if not, to what relief are the said workmen entitled?"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 74 of 1971 and notices were directed to the Workmen and the Management. On behalf of the Workmen a claims statement is filed by the General Secretary, Singareni Collieries Workers' Union, Kothagudem. It was inter alia alleged that as per the Wage Board Recommendations no Welders should get less than Category-V wages but the Management while implementing the recommendations gave new Category-IV wages to all the Welders in all the Divisions instead of new Category-V wages. Thus the five workmen mentioned in the reference are said to have been Category-IV swage instead of Category-V wages. These five workmen are said to be qualified Welders and are working independently on the jobs allotted to them either as Electrical Welders or in Gas Welding Section. It is reiterated that as per Appendix-V of the Wage Board Recommendations under Item Time Rated Categories/designations and job description no Welders should get less than Category-V wages. The minimum starting pay of Welders is said to have been shown at serial No. 17 of Category-V. These Welders are said to have been working independently and were so found doing when the Assistant Labour Commissioner, Vijayawada made a spot check in the presence of the Management. Thus the demand for Category-V wages to these five workmen was sought to be justified.

3. In the counter filed by the Management it is inter alia urged that the present dispute is untenable in the light of the reference in Industrial Dispute No. 30 of 1967 wherein the modifications and changes in the various categories were referred for adjudication in the light of the Wage Board Recommendations as well as the agreements contained in paras 3 to 7 of Chapter IX of the Report relating to Andhra Pradesh. It is urged that while evolving a uniform wage structure for Coal Industry, the Wage Board took note of some differences in job description and job nomenclature in Singareni Collieries and with a view to resolve the differences deputed a Sub-Committee which assisted the parties to arrive at an agreed categorisation in respect of some jobs including Tradesmen. The discussion and the Agreements reached therein are said to have been referred to in paras 3 to 7 of Chapter IX of the Wage Board's report. The Wage Board directed that the categorisation applicable to Singareni Collieries is subject to these Board agreements. The agreement reached in respect of Tradesmen and Artisans is that workers in Categories-IV and V should be allotted to new Category-4, workers in Categories-VI and VII shall be allotted new Category-5, and workers in Categories-VIII and IX shall be allotted new Category 6. The Welders are said to be covered by this Agreement. It is thus contended that the agreement cannot be reopened and a claim for higher category with regard to Welders cannot be made on the basis adopted for allotment of new Categories in Bengal and Bihar. Thus the placement of five workmen in New Category-IV is said to be strictly in conformity with the agreement. Thus the agreements which were taken note of by the Wage Board are said to be conclusive. In fact it is contended that even the reference in Industrial Dispute No. 30 of 1967 specifically refers to the modifications and changes in categorisation subject to these agreements. Thus the claim in I.D. No. 30 of 1967 is said to cover the Welders also. This reference is therefore said to be bad in law and would fore-stall the decision in I.D. No. 30 of 1967. The other contention is that Company is running heavy loss year after year and it is not possible to meet the new demands for higher categorisation. The job description and job nomenclature of Welders under the Coal Award and the Wage Board are said to be identical. The Coal Award placed Welders in Old Categories-VII and IX which are equivalent to new Categories-5 and 6. Under the Tradesmen agreement of 1961 when more number of mines were working at Kothagudem it was agreed to have one Master-Grade Welder, one Welder in old Category VIII (which is equivalent to new Category 6) and two in old Category VII (which is equivalent to new Category 5). Thus the requirement of the Management is said to be two Welders in new Category 6 and two Welders in new Category 5. As against this strength provided, there are said to be at present three Welders in new Category 6 and five Welders in new Category 5, apart from the five workmen in dispute who are said to be in new Category 4. The production capacity is said to have been curtailed and mines which were existing in 1961 at Kothagudem were closed down and only three mines are working at present. As a cumulative effect of this development, the strength of Welders as provided under the Tradesmen Agreement, is said to be high and the strength of the Welders in higher categories is more than the strength provided under the agreement. It is thus contended that there is no justification for creating more posts in higher categories. With regard to Trade Apprentices who are subsequently absorbed in old Category IV, the same Union is said to have raised a dispute in respect of three Welders formerly in Category IV contending that Category VII was to be allotted to them under the Coal Award. That dispute is said to be the subject matter of I.D. No. 66 of 1965. Noorul Rahiman, one of the workman mentioned in the reference was also a concerned workman in that dispute. The Tribunal in its award is said to have rejected the claim of the workmen therein holding that they cannot claim Category VII by mere afflux of time and that promotion depended upon the passing of test and the availability of vacancies. A similar dispute raised by the Andhra Pradesh Colliery Mazdoor Sangh in respect of some other workers including Welders (all in old Category IV) claiming old Category VII referred for adjudication in I.D. No. 17 of 1966 is said to have been withdrawn. It is thus contended that the present demand virtually amounts to creation of new posts which cannot be matter of an industrial dispute. In view of the Award in I.D. No. 66 of 1965 relating to the higher categories for Welders, the same Union is estopped from raising the dispute for higher category. The strength of Welders is said to be more than the requirement. Thus the services of Dharma Raj and Sofi who were on probation were re-trenched in the year 1967 but they were taken back as per the decision of the Tribunal in Industrial Dispute Nos. 38 and 48 of 1968. It is however urged that in the light of the earlier award there is no justification for retaining those people in old Category IV. The Workmen on being promoted to new category 4, from old category IV are said to benefit by 50 per cent increase in their emoluments. It is however contended that after discussions with the Union two voluntary retirement Schemes were introduced in the year 1968 and 1969 under which a large number of surplus workers were retired with benefits. It is denied that the five workmen were carrying out the work independently or that it was so found by the Assistant Labour Commissioner during his visit to the spot. Thus the workmen are said to be carrying out miscellaneous jobs which do not require skill in welding. In short it is contended that considering the nature of jobs and the work load there is no need for continuing the five workmen. Thus the demand is resisted.

4. On behalf of the Workmen W.W. 1 to W.W. 4 were examined in oral evidence and Exs. W1 to W16 are marked in documentary evidence. In rebuttal M.W. 1 is examined and Exs. M1 to M4 are marked by way of documentary evidence.

5. During the enquiry the parties reported that this dispute along with various other demands were referred to the Hon'ble Minister for Labour of the Central Government for his decision. They sought time awaiting his decision. On 7-6-1974 a joint Memo is filed by the parties to the effect that an award in terms of the Settlement be passed. A copy of the decision of the Hon'ble Minister is also made available to the Tribunal. It is seen that a decision is given with regard to various categories and demands numbering 84 in all. The cases of Welders is said to be covered by item Nos. 13 and 43 of the said decision. A perusal of the Settlement would disclose that all the five workmen mentioned in the reference are given Category V with effect from 1st June, 1974. This Settlement is signed by the General Secretary of the Union which was espousing the cause of the five workmen. The Settlement has also been recorded on 16-9-1974. Incidentally the General Secretary of Tandur Coal Mines Labour Union who was also present reported no objection. Before accepting a Settlement as the basis of an award the Tribunal has to examine whether the terms of the Settlement are fair and reasonable. It can however be noted that the decision given by the Hon'ble Minister which covers matters that are the subject matter in I.D. No. 30 of 1967 is a comprehensive one. I need not even advert to the question of reasonableness or fairness of this Settlement for the obvious reason that the demand of the five workmen mentioned in the reference is substantially met by the Management. It cannot for a moment be said that the

Settlement is in any way prejudicial to the interest of the Workmen. It is true that there is a clause in the Settlement with regard to the liability of the workmen to be transferred to any Division as and where vacancies are available, but that clause cannot be said to be in any way against the interest of the workmen. Since the demand of the workmen is substantially met no question of the Settlement being reasonable or fair would arise in the circumstances. In this view of the matter the Settlement can be accepted as the basis of an award.

5. In the result, award is passed in terms of the Settlement. A copy of the Settlement be enclosed to this Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 20th day of September, 1974.

Appendix of Evidence

Witness examined for Workmen.	Witness examined for Management.
W.W. 1 Shaik Mastan	M.W. 1 V. R. Sunder Rajan
W.W. 2 G. Papaiah	
W.W. 3 M. Dharmaraju	
W.W. 4 C. R. Dhanraj	

Documents exhibited for Workmen

- Ex. W1 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 3-1-1972.
- Ex. W2 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 1-4-1972.
- Ex. W3 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 6-4-1972.
- Ex. W4 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 16-4-1972.
- Ex. W5 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 12-4-1972.
- Ex. W6 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 15-4-1972.
- Ex. W7 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 21-4-1972.
- Ex. W8 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 22-4-1972.
- Ex. W9 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 26-4-1972.
- Ex. W10 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 27-4-1972.
- Ex. W11 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 3-5-1972.
- Ex. W12 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 11-5-1972.
- Ex. W13 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 25-5-1972.
- Ex. W14 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 30-5-1972.
- Ex. W15 Work allocation register showing the work done by the Welders and carpenters during the period 27-5-1969 to 19-7-1967.
- Ex. W15(a) Marked portion showing the work done by Sri Laxmaiah in the 1st shift on 29-5-1969 at page 13 of the work allocation register i. e. Ex. W. 15.

- Ex. W15(b) Marked portion showing the work done by Sri Mastan and Noorul Rehiman in the 2nd shift on 29-5-1969 at page 13 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.
- Ex. W15(c) Marked portion showing the work done by Sri Laxmaiah on 30-5-1969 at page 19 of the work allocation register i.e. Ex. W.15.
- Ex. W15(d) Marked portion showing the work done by Sri Mastan in the 2nd shift on 30-5-1969 at page 19 of the work allocation register i.e. Ex. W.15.
- Ex. W(e) Marked portion showing the work done by Sri Nurul Rehiman on 30-5-1969 at page 19 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.
- Ex. W15(f) Marked portion showing the work done by Sri Iyulu on 2-6-1969 at page 29 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.
- Ex. W15(g) Marked portion showing the work done by Sri Mastan in 2nd shift on 3-6-1969 at page 29 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.
- Ex. W15(h) Marked portion showing the work done by Sri Nurul Rahiman and Sri T. Venkateswar Rao on 3-5-1969 at page 35 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.
- Ex. W15(i) Marked portion showing the work done by Sri Laxmaiah in the 2nd shift on 3-6-1969 at page 35 of the work allocation register i.e. Ex. W.15.
- Ex. W15(j) Marked portion showing the work done by Sri Mastan on 3-6-1969 at page 35 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.
- Ex. W16. Work allocation register showing the work done by the carpenters and welders etc., for the period 10-4-1969 to 24-5-1969.

Documents exhibited for Management

- Ex. M1 Copy of the Tradesmen agreement dt. 3-2-1961.
- Ex. M2 Copy of the Award of the Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad in I.D. Nos. 38 & 48 of 1968 dt. 16-8-1969.
- Ex. M3 Copy of the Award of the Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad in I.D. No. 66/64 dt. 26-6-1967.
- Ex. M4 Memoandum of Settlement arrived at between the Management of Singareni Collieries company Limited, Kothagudem and their workmen represented by the A. P. Colliery Mazdoor Sangh, Kothagudem in I.D. No. 17/66 dt. 6-10-1967.

Sd/-

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT UNDER SECTION 18(1) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT 1947 BETWEEN THE MANAGEMENT OF THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY THE SINGARENI COLLIERIES WORKERS' UNION ON 7TH JUNE, 1974 AT KOTHAGUDEM.

Parties Present :

Representing Management :	Representing Workmen :
(Singareni Collieries Company Limited.)	(Singareni Collieries Workers' Union).
1. Shri M. K. V. Subbaiah, Dy. General Manager.	Shri M. Komaraiah, General Secretary.
2. Shri N. Bhaskarachary, Chief Personnel Officer.	

SHORT RECITAL OF THE CASE

The demand of the Singareni Collieries Workers' Union for placing S/Shri Sk. Mastan, Noorul Rahiman, M Dharma Raj, T. Venkateswarlu and Sofi, Welders of Cat IV, Main workshop, Kothagudem in Category V was referred for adjudication to the Industrial Tribunal (Central), Hyderabad and numbered as I.D. 74/71

While the Union in their claim statement relied on the categorisation of the workers under the Wage Board in Bengal and Bihar, the Management contended that the categorisation of Tradesmen which includes Welders was discussed before the Sub Committee of the Wage Board in February 1966 as per which it was agreed that the Tradesmen in old Categories IV and V will be placed in new Cat IV under the Wage Board and the workers will have no claim to reopen these issues that a particular category of workmen would get a higher category on the basis of allotment of new categories adopted in Bengal and Bihar. The evidence in this case on both sides has been concluded and arguments are yet to be heard for passing an Award. In the meantime, the Unions have raised the issue relating to categorisation of Welders etc., in general before the Union Labour Minister demanding that they should be paid not less than Cat. V and agreed to abide by his decisions.

The claim of the workmen in dispute has been reviewed in the light of the decision of the Union Labour Minister against Demand No. 13 relating to Tradesmen and Demand No. 43 relating to Welders, Mechanics and Armature Winders etc., and Tradesmen Agreement now in force.

In accordance with the Tradesmen Agreement now in force, the strength of Welders in the Main Workshops is much in excess of the requirements. As against two Welders in Cat VI and two Welders in Cat V, the present strength is two Welders in Cat VI, five Welders in Cat V and four Welders in Cat IV. Thus, there are three surplus Welders in Cat V in addition to four Cat IV Welders involved in the present dispute. Having regard to the substantial number of surplus Welders on rolls, the Management pointed out that the claim of the workmen in dispute for placing them in Cat V can only be considered against vacancies that may arise in future.

The dispute has been discussed in all its aspects and without prejudice to the relative contentions in I.D. 74 of 71, the parties have agreed as under :—

Terms of Settlement

- (1) The Management has agreed as a special case to place S/Shri Sk. Mastan, Noorul Rahiman, M Dharma Raj, T. Venkateswarlu and Sofi, Welders of Cat IV, Main Workshop, Kothagudem in Cat V with effect from 1st June, 1974.
- (2) These workmen are liable to be transferred to any of the workshops in any Division as and where vacancies are liable.
- (3) The parties have agreed to file this Settlement as a compromise and request the Tribunal to pass an Award accordingly.
- (4) The Settlement will be implemented after Award in the dispute is passed by the Tribunal.

Terms of Settlement

Representing Management Representing Workmen

Sd/ (M K V Subbarah) Sd/- (M Komariah)

Sd/ (N Bhaskarachary)

Witnesses

1 Sd/- (V Gopala Sastry)

Asst Personnel Officer, C P O's office

S C Co Ltd, Kothagudem

2. Sd/- (P Satyanarayana)

Office Assistant, C P O's office,

S C Co Ltd, Kothagudem

Dated 7th June, 1974

Kothagudem Collieries

TRUE COPY

T NARSING RAO, Industrial Tribunal

[No. L 21012/25/71-LR II]

LALFAK ZUALA Dy. Secy

अम सत्रालय

आदेश

सई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1974

का० प्रा० 3046 —यन केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स कान्टीनेन्टल कस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, विशाखापत्तनम के प्रबन्धतत्त्व से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यन केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है,

अतः अद्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे जिसका मुख्यालय हैदराबाद होगा और उक्त विवाद का उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मेसर्स कान्टीनेन्टल कस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, विशाखापत्तनम का मस्टर रोल कर्मचारियों को वर्ष 1971 के लिए और दैनिक मजदूरी तथा मस्टर रोल कर्मचारियों को वर्ष 1972 तथा 1973 के लिए बोनस न देना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किय अनुपात के हकदार हैं?

[स० एन-34011/14/74 पी हा/सी एस टी]

ORDER

New Delhi, the 19th October, 1974

S O. 3046.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Continental Construction (Private) Limited, Visakhapatnam and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether Messrs. Continental Construction (Private) Limited, Visakhapatnam are justified in denying payment of bonus to muster roll workers for the year 1971 and to daily rated and muster roll workers for the years 1972 and 1973? If not at what rate are these workmen entitled?"

[No L-34011/14/74-PD/CMT]

New Delhi, the 7th November, 1974

S.O. 3047.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs International Construction Corporation, Karanja and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd October, 1974.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL, BOMBAY.

Reference No. CIT-7 of 1971

Parties :—

Employers in relation to the management of M/s. International Construction Corporation, Karanja.

and

their workmen.

Appearances :

For the employers—Shri S. A. Sanzgiri, Advocate
For the workmen—Mrs S. V. Navalkar, General Secretary

State.—Maharashtra Industry.—Major Ports and Docks.

Bombay, dated 20th September, 1974

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour and Employment have in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by their Order No. I 29011/33/71-LR-IV dated 22-10-1971 referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs International Construction Corporation, Karanja and their workmen in respect of the matters specified in the following schedule:—

SCHEDULE

"Whether the workmen of Messrs. International Construction Corporation, Karanja Uran are entitled to any compensation for the strike period commencing from the 7th August, 1971? If so, with what details?"

2. Messrs. International Construction Corporation the employers in this reference had raised a preliminary objection challenging the validity and competence of the reference and jurisdiction of this Tribunal. My learned predecessors by his order dated 26th February 1973 had held that the work done by the employers was in relation to a major port and the dispute concerns an industry carried on by the Central Government and it concerned a major port and hence the Central Government was the appropriate Government to make the reference and this Tribunal had jurisdiction

3. The United Labour Union representing the workmen by their statement of claim stated that the company employed more than 125 workmen in various categories; that the wages normally paid to the workmen on the 7th of each month were not paid for the month of July 1971 till August 11

1971 and consequently the workmen started their demonstration from 9-8-1971. The company it is contended put up a notice that non-payment period will be treated as lay-off and wages would be paid accordingly. It is submitted that during the demonstrations wages for the period of July 1971 were paid but subsequent wages were not paid. It is further submitted that the workmen demanded full wages from 7th to 11th August 1971 and the matter was referred to the Assistant Labour Commissioner (Central), Bombay. But the management was adamant and the agitation continued. The workmen it is contended were prepared to resume work on completion of the conciliation proceedings but the management refused to provide work. The strike therefore continued and according to the union their action was legal. The Union further contends that on 25-12-1971 the company issued notices to the workmen informing that their services were not required because the principal company M/s. Ivan Milutinovic Pim were not supplying raw materials and were not paying the company's dues. The company thus abruptly retrenched the workmen and the unions case is that it was illegal unjust and mala fide. The workmen therefore claimed full wages from 1-8-1971 to 25th January 1972 and retrenchment compensation and notice pay. In a note at the end of the statement of claim it is submitted that the strike commenced after the 2nd shift on 10-8-1971 and ended on 1st shift on 10-11-1971.

4 The company by their written statement has contended that Messrs. Ivan Milutinovic Pim and Co. a company with had office in Yugoslavia and a site head office at Bombay whom they call as principal contractor was entrusted by the Government of India the work of construction of the new break water wharf at Karanja, Uran (District Kolaba). It is submitted that the principal contractor provided stones and boulders from their quarry at Karanja to the sub-contractor, the employers herein, for the said job of breaking and crushing stones and finished materials to be supplied back to the principal contractor that under the terms of contract the principal contractor, has control and supervision for payment of wages etc. to the workmen of the sub-contractor as also security arrangements of entry into and exit from the place of work of the workmen of the sub-contractor. The company contends that the reference is not maintainable in law as the same is vague and uncertain as there was no strike on 7th August 1971. Without prejudice to the above it is submitted that the company is not a proper party as it not responsible for payment of any dues of the workmen. Again without prejudice it is submitted that the statement of claim is not filed by the authorised person and the alleged industrial dispute is not raised by the workmen of the company. On the merits it is submitted that the alleged strike was illegal as according to the workmen the strike was caused due to the delay in payment of the monthly wages of the workmen. The strike was also in violation of an agreement dated 29-3-1971 wherein it was specified that the men would not go on strike without giving 15 days notice. According to the company payment was made to the workers on 7-8-1971 but on 9-8-1971 the workmen demonstrated that there was delay in payment and on 12-8-1971 they went on strike. The parties sought the intervention of the Labour Commissioner (Central) and as there was no settlement a failure report was submitted on 3-9-1971. Although the union was advised by the Conciliation Officer both orally and in writing to call off the strike his advice was not heeded and the conciliation ended in failure. The company by their notice dated 4-9-1971 called upon the workers to resume duty but the workmen did not respond. It is further submitted that in the meantime the principal contractor wrongfully terminated their agreement with the present company and as such the company had no alternative but to terminate the services of their workmen. The company has stated that there are only 23 workmen employed by them and not 125 as alleged by the union. They have denied that there was any delay in payment of wages as alleged; in fact because the principal contractor did not supply them with raw materials etc. the company had no option but to lay off certain workmen. The company has further denied the allegations of the union regarding non-payment of wages and announcement of lay off. It is submitted that the action of the workmen is not legal; in fact the employers by their letters dated 12th and 13th August 1971 called upon the workmen to resume duty as the strike was illegal under the agreement dated 29-3-1971. The company says that are always willing to employ the workmen as per agreement arrived at in conciliation but at times they were forced to lay off workmen as there was no raw material supplied by their principal contractor Messrs. Pim and Co.

5. In view of the pleadings of the parties the following issues arise for consideration :—

- (1) What were the number of workmen employed by International Construction Company?
- (2) What was the duration of the strike?
- (3) Whether the strike was legal and valid and if so, what is the compensation to be paid to the workmen?

After the order on the preliminary objection both the workmen and the employers examined one witness each. The workmen tendered in evidence exhibits W-1 to W-33 and the employers E-1 to E-16.

6. ISSUE No. 1.—It is stated by the workmen in their statement of claim that the International Construction Corporation employs more than 125 workmen in various categories. They have submitted a list of 89 workers. The employers on the other hand contend that there are only 23 workmen under them. In support of their claim that only 23 workmen are employed by them they have filed exhibits E-1 to E-5. It is deposed by EW-1 that in August 1971 there were 31 workmen employed by them including the Bombay office. Exhibits E-1 to E-3 are the muster rolls and exhibits E-4 and E-5 are the payment registers. The evidence placed on record does not bear out that there were 23 workmen employed by the International Construction Company. In the proceedings before the Conciliation Officer dated 26-8-1971 it is noted that the management stated that out of about 113 workmen 51 are ready to start the work and they are not attending the work because of fear of assault. In their letter dated 30-8-1971 addressed to the Assistant Labour Commissioner the employers had stated that 113 workmen were employed by the International Construction Corporation, M.J.V. Bhatt & Co., and Vasa and Co. It is stated by EW-1 that he was managing all the affairs of the I.C.C. and the other companies. M/s. Vasa & Co., and M/s. Bhatt & Co. were their sub-contractors and he was the partner of Vasa & Co., but not a partner of Bhatt & Co. Exhibit E-7 shows that EW-1 had signed the settlement on behalf of Vasa & Co. and M.J.V. Bhatt & Co. It is also clear from the materials placed on record that 113 workmen were employed by the International Construction Corporation and this issue is answered accordingly.

7. ISSUE No. 2.—The employers contend that there was no strike on 7th August but the strike commenced on 12-8-1971. It is deposed by EW-1 that on 7-8-1971 they made payments to all the hammermen as 8th was a Sunday-holiday and the mechanical staff was paid on 11-8-1971. On 12-8-1971 they received the raw material and the lay off ended but the workers did not report for duty and although the workers were asked to report for duty they continued their strike and the workers refused to work from 12-8-1971. It is stated in the letter of the United Labour Union addressed to the Assistant Labour Commissioner dated 13th August 1971 that from 9-8-1971 the workers sat down in front of their office for their salary and the management had put a notice on their notice board of the non-period as lay-off for their staff only. It appears from letter dated 27-8-1971 from the President, United Labour Union to the works Manager, Ivan Milutionovic Pim that since the payment for the month of July 1971 had not been paid on due date i.e. 7-8-1971 a section of their employees in protest to the late payment have stopped their duty on 9-8-1971 and in favour of their requisite justice all other employees joined them 11-8-1971 where as the employers in their letter dated 4-9-1971 (exhibit W-26) have adverted to their sympathetic and humanitarian attitude which they displayed to bring about a settlement and their agreement to pay the workers one hour per day wages for the strike period of 12-8-1971 to 31-8-1971. But from the oral and documentary evidence placed before me it can be concluded that the strike commenced on 9-8-1971. Now it has to be seen up to what period the strike continued. The International Construction Corporation by their letter Exhibit W-9 dated 7-12-1971 informed the Assistant Labour Commissioner that pursuant to their discussion with him on 2-12-1971 their workmen ended their illegal strike and reported on work on 7-12-1971 and they took them back on work on the same day. Similarly by exhibit W-10 dated 6-12-1971 the International Construction Corporation informed the Chief Engineer of M/s. Ivan Milutionovic Pim that they were pleased to inform them that their illegally striking workmen had agreed to resume their normal duties and hence they would be able to start their work on 7-12-1971. In the letter dated 17-11-1971 exhibit W-11 the Presi-

dent of the United Labour Union informed the Regional Labour Commissioner (Central) that all the workmen reported for duty on 10-11-1971. This fact is also borne out by the letter dated 8-11-1971 exhibit W-13 in which the General Secretary of the United Labour Union informed the Regional Labour Commissioner (Central) Bombay that the workmen reported for duty on the conclusion of the conciliation proceedings with the Assistant Labour Commissioner. It is testified by W-1 that on 2-12-1971 there was an agreement in the labour office by which the workers agreed to resume duties on 7-12-1971. Exhibit E-9 the memorandum of settlement shows that the management had already started the work with effect from 7-12-1971 and all the workmen were marked present in the muster roll. In view of this voluminous documentary and oral evidence it can safely be posited that the strike ended on 6-12-1971. The duration of the strike therefore is from 9-8-1971 to 6-12-1971.

8. It is contended by the learned Counsel on behalf of the workmen that according to the understanding reached between the union and the management they had to make payment to the workers on the 7th and 22nd of every month but the management failed to make the payment on the due dates. In the month of July they made the payment on the 10th and in the month of Aug. the payment was made on 11th. The employees had gone on strike on the 9th and the management laid off the workers on 10th and 11th August, 1971. This lay off by the employers was unjustified and illegal and the lay off was not in compliance with the statutory rules and regulations and they did not inform the Labour Commissioner about the lay-off. It is further pointed out that under exhibit E-7 the management had agreed not to declare lay-off lock-out without serving notice to that effect to the parties and authorities concerned in accordance with the procedure laid down by the appropriate statutes. But the validity of the lay-off or otherwise is not subject matter of reference before me and therefore no pronouncement on that subject is invited. The only question to be answered is whether the strike was legal.

9. ISSUE NO. 3.—In order to answer the issue reference is necessary to certain provisions of the Industrial Disputes Act. Under section 22 of the Industrial Disputes Act no person employed in a public utility service shall go on strike in breach of contract without giving to the employer notice of strike as hereinafter provided within six weeks before striking; or within 14 days of giving such notice or before the expiry of the days of strike specified in any such notice as aforesaid; or during the pendency of any conciliation proceedings before a Conciliation Officer and seven days after the conclusion of such proceedings. Section 24 provides that a strike or lock-out shall be illegal if it is commenced or declared in contravention of section 22 or section 23; or it is continued in contravention of an order made under sub-section (3) of section 1 or sub-section (4-A) of section 10-A. The rest of the provisions need not be referred to as they are not relevant to our purpose. Under exhibit E-7 memorandum of settlement dated 29-3-1971 the union had agreed not to resort to direct action without serving 15 days notice to the management as prescribed under the existing rules and regulations to the effect. No notice of the strike was served on the employers either under exhibit E-7 or under section 22 of the Industrial Disputes Act which renders the strike by the employees to be illegal. There is another factor which renders the strike illegal. Admittedly conciliation proceedings were pending before the Conciliation Officer from 23-8-1971 on a request made by the workman on 18-8-1971 and the conciliation proceedings continued till 1st September, 1971. This is borne out from the report of the Conciliation Officer. It is true that the strike had already commenced from 9-8-1971 and the conciliation proceedings had commenced on 23-8-1971. Section 24 of the Industrial Disputes Act clause (2) will not be attracted as this section will be applicable only where a strike or lock-out in pursuance of an industrial dispute had already commenced and was in existence at the time of the reference of the dispute to a Board, an Arbitrator, a Labour Court, Tribunal or National Tribunal and the continuance of the strike or lock-out shall not be deemed to be illegal. Here the reference is not to a Arbitrator or Industrial Tribunal but the dispute was referred to the Conciliation Officer. Therefore the continuance of the strike by the workmen after the Conciliation Officer was seized of the dispute i.e. from 23-8-1971 to 1st September, 1971 and during its pendency was certainly illegal and it comes within the mischief of clause (d) of section 22. Viewed in any context the conclusion is irresistible that the strike by the workmen from 9th August to 7th December, 1971 was illegal and invalid. This issue is answered accordingly.

New Delhi, the 30th October, 1974

As the strike is held to be illegal no question of awarding any compensation to the workmen arises and the reference is answered accordingly.

No order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer.

[No. L-29011(33)/71-LR. IV]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3018.—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेंट जोसेफ्स मिशन हॉस्पिटल, अंचल पोस्ट आफिस, क्विलोन जिला, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाती है ।

[सं० ए० 35019(160)/73-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 28th October, 1974

S.O. 3048.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs St. Joseph's Mission Hospital, Anchal Post Office, Quilon District, Kerala have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1973.

[No. S. 35019(160)/73-PF. II]

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3049.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री आर० पी० देवूचकर को उक्त अधिनियम और स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके निर्भरताधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महा पत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएँ हों, सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० ए० 12016(3)/74-पी० एफ०-1]

S.O. 3049.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri R. P. Dewoolkar to be an Inspector for the whole of the State of Maharashtra for the purposes of the said Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(3)/74-PF. I]

नई दिल्ली, तारीख 1 नवम्बर, 1974

का० आ० 3050.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3091 तारीख 5 नवम्बर, 1972 को अधि-कृत करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री ए० एम० मन्नाथन् के स्थान पर श्री आर० एम० गांधी को, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए, सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त करती है ।

[सं० ए० 12016(8)/74-पी० एफ० 1(i)]

New Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3050.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3091, dated the 5th September, 1972, the Central Government hereby appoints Shri R. M. Gandhi as Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the State of Madhya Pradesh to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties, vice Shri A. S. Sattanathan.

[No. A-12016(8)/74-PF.I(i)]

का० आ० 3051.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3092 तारीख 5 नवम्बर, 1972 को अधि-कृत करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री आर० एम० गांधी को उक्त अधिनियम स्कीम और उनके अधीन विरचित कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उनके निर्भरताधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जिसके एक से अधिक राज्यों में विभाग या शाखाएँ हों, सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० ए० 12016(8)/74-पी० एफ० 1(ii)]

S.O. 3051.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3092, dated the 5th September 1972, the Central Government hereby appoints Shri R. M. Gandhi to be an Inspector for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(8)/74-PF. I(ii)]

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1974

क्रा० आ० 3052.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एन० थिरुवेन्कटाथन को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित स्कीम और कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के या उसके नियन्त्रणाधीन किसी स्थापन के सबंध में या किसी रेल कम्पनी महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियन्त्रित उद्योग से सम्बंधित किसी स्थापन के सबंध में या किसी ऐसे स्थापन के सबंध में, जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग और शाखाएँ हों, सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य और पाण्डिचेरी संघीय क्षेत्र के निम्ने निरोधक नियुक्त करती है।

(स० ए० 12016(6)/74-पी० एफ० 1)

आर० पी० नरुला,

अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 1974

S.O. 3052.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri N. Thiruvengatathan to be an Inspector for the whole of the State of Tamil Nadu and the Union territory of Pondicherry for the purposes of the said Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(6)/74-PF. I]

R. P. NARULA, Under Secy

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

क्रा० आ० 3053.—यत् केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) में उपखंड (vi) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिवृत्तना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिवृत्तना संख्या क्रा० आ० 1191 तारीख 30 अप्रैल, 1974 द्वारा किसी तेल क्षेत्र में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 मई, 1974 से छ मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और यत् केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 नवम्बर 1974 से छ मास की और अवधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[क्रा० सं० 11025/18/74-एन० आर० 1]

New Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3053.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provision of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1191 dated the 30th April, 1974 service in any oil-field, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 22nd May, 1974;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said service to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd November, 1974.

[F. No. S. 11025/18/74-LR. I]

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1974

क्रा० आ० 3054.—यत् केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परन्तुक के अनुसरण में एक अधिवृत्तना सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिवृत्तना संख्या क्रा० आ० 1141 तारीख 24 अप्रैल, 1974 द्वारा भारत सरकार टंकसाह, अलीपुर, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 10 मई, 1974 से छ मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था,

और यत् केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 10 नवम्बर, 1974 से छ मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[क्रा० सं० ए० 11025/17/74-एन० आर० 1]

ए० ए० महानामन, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd November, 1974.

S.O. 3054.—Whereas the Central Government being satisfied that public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1141 dated the 24th April, 1974, the India Government Mint, Alipore, Calcutta, to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months from the 10th May, 1974,

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 10th November, 1974.

[F. No. S. 11025/17/74-I R. 1]

S. S. SAHARANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

क्रा० आ० 3055.—बीनम संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिस्तुत करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई मारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उसके स्तंभ (2) में की तत्त्वानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

मारणी,

अधिकारी	सीमाएं
(1)	(2)
I 1 मुख्य श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली। 2 उप मुख्य श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली। 3 प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली। 4 मुख्य श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय) का कल्याण-सलाहकार, नई दिल्ली। 5 सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली। 6 श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), नई दिल्ली।	सम्पूर्ण भारत।
II. 1. प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई। 2 मुम्बई क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 मुम्बई क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।	महाराष्ट्र राज्य और गोवा, वसण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
III. 1. प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता। 2 कलकत्ता क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 कलकत्ता क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।	पश्चिमी बंगाल (बर्दवान, बिरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिलों को छोड़ कर), असम, मेघालय, सागानैड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और मिजोराम, छत्तुगचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र।

(1)	(2)
IV 1 प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), मद्रास। 2 मद्रास क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 मद्रास क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।	तमिलनाडु और केरल राज्य तथा पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र तथा कर्नाटक, राज्य में बंगलूर, कोलार, मैसूर, माण्डवा, टुंकर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, हुसन, चिकमगल, शिमोगा, चित्रदुर्ग और आंध्र प्रदेश में चित्तूर के सिविल जिले।
V. 1. प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर। 2 जबलपुर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 जबलपुर क्षेत्र के सभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4 जबलपुर क्षेत्र के सभी कनिष्ठ श्रम-निरीक्षक (केन्द्रीय)।	मध्य प्रदेश राज्य
VI. 1. प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर। 2 कानपुर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 कानपुर क्षेत्र के सभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4 कानपुर क्षेत्र के सभी कनिष्ठ श्रम-निरीक्षक (केन्द्रीय)।	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर राज्य तथा दिल्ली और झण्डा राज्य क्षेत्र।
VII. 1. प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद। 2 धनबाद क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 धनबाद क्षेत्र के सभी कनिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4 धनबाद क्षेत्र के सभी कनिष्ठ श्रम-निरीक्षक (केन्द्रीय)।	बिहार राज्य
VIII. 1 प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद। 2 हैदराबाद क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 हैदराबाद क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4 हैदराबाद क्षेत्र के सभी कनिष्ठ श्रम-निरीक्षक।	कर्नाटक राज्य (बंगलूर, कोलार, मैसूर, माण्डवा, टुंकर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, हुसन, चिकमगल, शिमोगा, चित्रदुर्ग के सिविल जिलों को छोड़ कर) और आंध्र प्रदेश (चित्तूर के सिविल जिले को छोड़ कर)।
IX. 1. प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), अजमेर। 2 अजमेर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 अजमेर क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।	राजस्थान और गुजरात राज्य
X. 1. प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), आमनसोल। 2 आमनसोल क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 आमनसोल क्षेत्र के सभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4 आमनसोल क्षेत्र के सभी कनिष्ठ श्रम-निरीक्षक (केन्द्रीय)।	पश्चिमी बंगाल राज्य में बर्दवान, बोरभूम, बांकुरा और पुरुलिया जिले।
XI. 1. प्रादेशिक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर। 2 भुवनेश्वर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3 भुवनेश्वर क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।	उड़ीसा राज्य।

[स०एस० 33012/6/74-डब्ल्यू०बी०]

जे० आर० आम्बी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st November, 1974

(1)

(2)

S. O. 3055.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), and in supersession of all the previous notifications on the subject, the Central Government hereby appoints the officers specified in column (1) of the Table below, to be Inspectors for the purposes of the said Act within the limits specified in the corresponding entry in column (2) thereof:

TABLE

Officers	Limits
(1)	(2)
I. 1. Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi. 2. Deputy Chief Labour Commissioners (Central), New Delhi. 3. Regional labour Commissioners (Central), New Delhi. 4. Welfare Adviser to the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi 5. Assistant Labour Commissioners (Central), New Delhi 6. Labour Enforcement Officers (Central), New Delhi.	Whole of India
II. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Bombay. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Bombay Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central), in the Bombay Region.	The State of Maharashtra and the Union Territory of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
III. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Calcutta Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central), in Calcutta Region.	The States of West Bengal (excluding the Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia) Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and the Union Territories of Andaman, and Nicobar Islands, Mizoram and Arunachal Pradesh.
IV. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Madras. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Madras Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Madras Region.	The States of Tamil Nadu and Kerala and the Union Territories of Pondicherry and Lakshadweep and the Civil Districts of Bangalore/Kolar/Mysore/Mandya/Tumkur/Coorg/South Kanara/Hasan/Chickmagalur. Shimoga) Chitradurg in the State of Mysore and Chittoor in the State of Andhra Pradesh
V. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Jabalpur Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Jabalpur Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central), in the Jabalpur Region.	The State of Madhya Pradesh.

VI. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Kanpur Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Kanpur Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Kanpur Region.	The States of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir and the Union Territories of Delhi and Chandigarh.
VII. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Dhanbad Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central), in the Dhanbad Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Dhanbad Region.	The State of Bihar.
VIII. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Hyderabad Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Hyderabad Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Hyderabad Region.	The States of Karnataka (excluding Civil Districts of Bangalore/Kolar/Mysore/Mandya/Tumkur/Coorg/South Kanara/Hasan/Chickmagalur/Shimoga/Chitradurg) and Andhra Pradesh (excluding the Civil District of Chittoor).
IX. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Ajmer Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Ajmer Region.	The State of Rajasthan and Gujarat
X. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Asansol. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Asansol Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Asansol Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Asansol Region.	The Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
XI. 1. Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Bhubaneswar Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Bhubaneswar Region.	The State of Orissa.

[No. S-33012/6/74-WB]

J.R. BAGCHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1974

क्र० प्र० 3056.—कर्मचारी राज्य बोमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग)

की अधिसूचना सं० 3222, तारीख 6 नवम्बर, 1973 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना-18 को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 9 अक्टूबर, 1974 से 8 अक्टूबर, 1975 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिये छूट देती है।

[फा० सं० 38014/55/73-एच० आई०]

टी० एस० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 1974

S.O. 3056.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 3222 dated the 6th November, 1973 the Central Government hereby exempts Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Poona-18 from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 9th October, 1974 upto and inclusive of the 8th October, 1975.

[S-38014/55/73-HU]

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

पूति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 1974

फा० आ० 3057.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 की 44) की धारा 34 की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 2 (8) विशेष सेल/69-एच०एस०-4 दिनांक 15 अक्टूबर, 1973 का आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियाँ सचिव, महाराष्ट्र सरकार, राजस्व एवं वन विभाग के द्वारा भी अपने कार्यों के अन्तर्गत आवासन पूल के अन्तर्गत आने वाली भूमि तथा सम्पत्तियों के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में प्रयोग की जा सकेंगी।

[संख्या 2(8)/विशेष सेल/69-एच०एस०-4]

दीन। नाथ असीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 30th August, 1974

S.O. 3057.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and in partial modification of the notification No. 2(8) Spl. Cell/69-SSIV dated the 15th October, 1973 of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 33 of the said Act shall be exercisable also by the Secretary to the Government of Maharashtra, Revenue and Forests Department, in addition to his own duties in respect of the lands and properties within that State and forming part of the 'Compensation Pool'.

[No. 2(8)/Spl. Cell/69-SS-IV]

D. N. ASHJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1974

फा० आ० 3058.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 की 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) तथा धारा 33 के अन्तर्गत प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियाँ पुनर्वास विभाग में निदेशक, श्रीमती कुसुम प्रसाद द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

[संख्या 60011(24)/74-(1)/प्रशासन-1]

न० वे० सुन्दररामन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 8th October, 1974

S.O. 3058.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (4) of section 24 and section 33 of the said Act shall be exercisable also by Shrimati Kusum Prasad, Director in the Department of Rehabilitation.

[No. 60011(24)/74-(i)/Admn. I]

N. V. SUNDRA RAMAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1974

फा० आ० 3059.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की 44 की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे तथा गुजरात सरकार के राजस्व विभाग में कार्य कर रहे संयुक्त सचिव को उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत उक्त मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपी गई शक्तियाँ सौंपते हैं; अर्थात्:—

(क) धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खरीद की बकाया राशि के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र जारी करना;

(ख) धारा 30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में आदेश जारी करना जिनसे भूमि के लगान की वसूल करने योग्य कोई बकाया राशि हो; और

(ग) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा ध्यान दिए जाने के लिए धारा 35, की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित शिकायत करना।

[संख्या 1(6)/72-विशेष सेल/एस० एस०-4]

न० वे० सुन्दरा रामन, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

ORDER

New Delhi, the 29th October, 1974

S.O. 3059.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint Secretary to the Government of Gujarat in the Revenue Department and exercising the powers of the Deputy Chief Settlement Commissioner, the powers conferred on the said Chief Settlement Commissioner under the following sections of the said Act, namely:—

(a) issuing a certificate under sub-section (3) of section 20 in respect of amount of purchase money remaining unpaid;

(b) making an order under sub-section (2) of section 30, in respect of persons from whom any sum is recoverable as arrears of land revenue; and

(c) making complaints as required by sub-section (2) of section 35 for enabling a Court to take cognisance of an offence punishable under the said Act.

[No. 1(6)/72-Spl. Cell/SS-IV]

N V SUNDRA RAMAN, Chief Settlement Commissioner

